CENGAGE

Cengage EXAM CRACK Series®

अर्थशास्त्र

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु

प्रशासनिक सेवाओं
की तैयारी में उपयोगी

prepmate®

अर्थशास्त्र

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु

CENGAGE

Australia • Brazil • India • Mexico • Singapore • United Kingdom • United States

CENGAGE

अर्थशास्त्र

© 2019 Cengage Learning India Pvt. Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher.

For permission to use material from this text or product, submit all requests online at
www.cengage.com/permissions

Further permission questions can be emailed to
India.permission@cengage.com

ISBN-13: 978-93-86668-89-9
ISBN-10: 93-86668-89-0

Cengage Learning India Pvt. Ltd.
418, F.I.E., Patparganj
Delhi 110092

Cengage Learning is a leading provider of customized learning solutions with office locations around the globe, including Australia, Brazil, India, Mexico, Singapore, United Kingdom and United States. Locate your local office at: **www.cengage.com/global**

Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education, Ltd.

For product information, visit **www.cengage.co.in**

Printed in India

विषय-सूची

प्राक्कथन *xxiii*
आभार-पूर्ति *xxv*
वीडियो-सूची *xxvii*
पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण *xxix*

1 आर्थिक वृद्धि और विकास 1

सकल घरेलू उत्पाद 1
सकल घरेलू उत्पाद क्या इंगित करता है? 1
सकल घरेलू उत्पाद की आलोचना 1
सकल घरेलू उत्पाद की गणना 1
भारत का स्थान (फरवरी 2018) 2
क्रय शक्ति समानता 2
नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर 3
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 3
बाज़ार मूल्य और कारक लागत 5
कारक लागत क्या है? 5
बाज़ार मूल्य क्या है? 6
बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध 6
सकल मूल्य संवर्धित या सकल घरेलू उत्पाद (कारक लागत) 6
सकल घरेलू उत्पाद के साथ संबंध 6
सकल मूल्य संवर्धित की गणना क्यों की जाती है? 7
आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक माप के रूप में जीवीए का उपयोग? 7
वैश्विक प्रवृत्ति क्या है? 7
सकल राष्ट्रीय उत्पाद 7
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है? 7
सकल घरेलू उत्पाद के साथ तुलना 8
शुद्ध घरेलू उत्पाद (बाज़ार मूल्य पर) 8
हम एनडीपी (Net Domestic Product) की गणना कैसे करते हैं? 8

राष्ट्रीय आय या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 8
प्रति व्यक्ति आय 8
आर्थिक वृद्धि का बेहतर माप कौन सा है: सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय? 10
आर्थिक विकास की परिभाषा 12
आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच महत्वपूर्ण अंतर 13
समावेशी वृद्धि 13
समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के दृष्टिकोण 13
लोरेंज वक्र 14
गिनी गुणांक 14
लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक, और असमानता माप 14
आर्थिक गतिविधि के स्तर से संबंधित शब्दावली 15
भारत में गरीबी अनुमान 16
तेंदुलकर समिति, 2005 (सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में) 16
रंगाराजन समिति 16
बेरोजगारी 17
बेरोजगारी के प्रकार 17
फिलिप्स वक्र 19
मानव संसाधन विकास 19
मानव विकास सूचकांक 20
मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए नई विधि 20
मानव विकास सूचकांक का मूल्य 21
बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21
संकेतक 22
सूचकांक की गणना 23
अभ्यास प्रश्न 23
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 30

2 भारत की कराधान प्रणाली 33

प्रतिगामी कर 33
समानुपाती कर 33
प्रगामी कर 33
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 34
निष्कर्ष 35
भारत में महत्वपूर्ण कर 35
आयकर 35
उत्पाद शुल्क 37

सीमाशुल्क 38
सेवा कर 38
बिक्री कर या वैट 38
कर राजस्व का वितरण 39
वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax, जीएसटी): अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में परिवर्तन 39
जीएसटी के घटक: राज्य वस्तु और सेवा कर (State Goods and Services Tax, एसजीएसटी), केंद्र वस्तु और सेवा कर (Central Goods and Services Tax, सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax, आईजीएसटी) 40
जीएसटी परिषद की संरचना 40
जीएसटी दर 41
जीएसटी के दायरे के बाहर वस्तुएं 41
राज्यों को मुआवजा 41
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण 41
ई-वे बिल 42
जीएसटी लाने के प्रभाव 44
जीएसटी का प्रशासन 44
जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट 45
इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए शर्तें 45
जीएसटी को लाने में चुनौतियां 46
कर-जीडीपी अनुपात 47
लाफर वक्र 47
न्यूनतम वैकल्पिक कर 48
यह क्यों होता है? 48
इन दो आयों में क्या अंतर हैं? 48
अभ्यास प्रश्न 50
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 54

3 मौद्रिक नीति 57

मौद्रिक नीति 57
मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध 57
मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन 57
मौद्रिक नीति के उपकरण 58
मात्रात्मक उपकरण 58

गुणात्मक उपकरण *62*
धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर बनाम आधार दर 63
धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर *63*
आधार दर *63*
भारतीय रिजर्व बैंक 64
भारतीय रिज़र्व बैंक के आठ प्रमुख कार्य *64*
बैंक खातों के प्रकार 65
पैसे की आपूर्ति (money supply) क्या है? 66
भारत में धन आपूर्ति की गणना *67*
आरक्षित धन की प्रासंगिकता क्या है? *68*
अभ्यास प्रश्न *69*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *74*

4 राजकोषीय नीति 79

उच्च व्यय और कम राजस्व संग्रह 79
कम व्यय और उच्च राजस्व संग्रह 79
राजकोषीय नीति का उपयोग 80
जब आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है *80*
जब अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है *80*
राजकोषीय नीति किसको प्रभावित करती है? 80
सरकारी घाटे का माप 81
राजस्व घाटा *81*
राजकोषीय घाटा *82*
प्राथमिक घाटा *82*
प्रभावी राजस्व घाटा *83*
घाटे की वित्त व्यवस्था 83
घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम *84*
क्या घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए? *84*
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 84
एफआरबीएम अधिनियम, 2003 पर वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव *85*
एफआरबीएम अधिनियम की आलोचना *85*
बजट 85
कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान लगाता है? *86*
आर्थिक सर्वेक्षण *87*
शून्य आधारित बजट *87*
निष्पादन बजट और परिणामोन्मुख बजट *87*

लैंगिक बजट *88*
प्रदर्शन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली *88*
बजट विश्लेषण *88*
बजट सुधार *91*
अभ्यास प्रश्न *93*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *97*

5 मुद्रास्फीति 101

मुद्रास्फीति के प्रकार 101
मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव 103
विभिन्न आर्थिक घटनावृत्त पर मुद्रास्फीति के प्रभाव 104
मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक 104
मुद्रास्फीति कटौती में आरबीआई की भूमिका *105*
उत्पादों के विभिन्न प्रकारों में मुद्रास्फीति 105
विकसित और विकासशील देशों में मुद्रास्फीति 106
मुद्रास्फीति के माप 106
मुद्रास्फीति सूचकांक *106*
मुद्रास्फीति की गणना *109*
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय 109
अभ्यास प्रश्न *110*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *114*

6 भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 117

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 117
वस्तुएं और सेवाएं 118
विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना 120
अर्थव्यवस्था में सामान्य संक्रमण 122
भारत की विकास गाथा का विशेष मामला: सेवा-नेतृत्व वृद्धि 123
माध्यमिक क्षेत्र में कम वृद्धि के परिणाम *124*
संगठित और असंगठित क्षेत्र 124
भारतीय संदर्भ *125*
अभ्यास प्रश्न *126*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *129*

7 उपादान 131

उपादान 131

प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष उपादान *131*

भारत में उपादान 131

खाद्य उपादान *132*

उर्वरक उपादान *134*

ईंधन उपादान *135*

कृषि उपादान 137

जल उपादान के प्रतिघात *137*

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 138

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 *139*

अंत्योदय अन्न योजना *139*

पीडीएस सुधार क्यों आवश्यक हैं? *140*

अभ्यास प्रश्न *141*

पिछली प्रारंभिक परीक्षा *143*

8 आधार 145

आधार अधिनियम 146

आधार लिंक कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति 147

आधार लिंक कार्यक्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 148

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का औचित्य 148

धारा 7 के तहत आधार अनिवार्यता को अलग क्यों माना जाता है? *148*

क्या आधार व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करता है? *148*

क्या चेहरा प्रमाणीकरण फर्जी हो सकता है? *149*

अभ्यास प्रश्न *150*

पिछली प्रारंभिक परीक्षा *150*

9 वित्तीय बाज़ार 151

मुद्रा बाज़ार 152

पूंजी बाज़ार 153

प्राथमिक बाज़ार और द्‌वितीयक बाज़ार 156

शेयर बाज़ार का विनियमन *156*

व्युत्पन्न 158

साझाकोष 160
लोड या नो-लोड कोष *160*
क्लोज-एंड कोष *161*
पेंशन कोष 162
शेयर बाज़ार से संबंधित शब्दावली 162
कंपनी 162
कंपनियों के प्रकार *162*
वित्तीय क्षेत्र विनियामक 163
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग *163*
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण *164*
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण *164*
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद *164*
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 165
तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियां: मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service), स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (Standard & Poor's), फिच (Fitch) *165*
भारत की क्रेडिट रेटिंग *165*
अभ्यास प्रश्न *167*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *172*

10 जनसंख्या 175

जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत 175
चरण I: उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर *175*
चरण II: कम मृत्यु दर और उच्च जन्म दर *176*
चरण III: कम मृत्यु दर और कम जन्म दर *177*
जनसंख्या घनत्व 178
शहरीकरण और आर्थिक विकास 180
जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को क्यों रोकती है? 181
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 182
परिवार नियोजन के लिए दृष्टिकोण 183
जनसंख्या को कम करने के लिए चीन की नीति 183
संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या अनुमान 184
अभ्यास प्रश्न *184*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *186*

11 भारतीय कृषि I: बाज़ार, सिंचाई, और वित्त 187

कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम 187
मंडी प्रणाली के उद्देश्य 187
पुराने एपीएमसी अधिनियम की समस्याएं 187
मॉडल एपीएमसी अधिनियम 189
मॉडल एपीएमसी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 189
मॉडल एपीएमसी अधिनियम में सुधार के लिए अतिरिक्त सुझाव 189
सिंचाई 190
भूतल सिंचाई 190
स्थानीयकृत सिंचाई 191
उप-सिंचाई या अधोभूमि सिंचाई 191
भारत में सिंचाई का प्रतिरूप 192
भारत में कृषि ऋण 193
कृषि ऋण के प्रकार 193
भारत में कृषि ऋण के स्रोत 193
कृषि ऋण का रुझान 195
ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की पहल 196
ग्रामीण ऋण संरचना में दोष 197
अभ्यास प्रश्न 198
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 200

12 भारतीय कृषि II: भूमि सुधार 203

भूमि सुधार 204
बिचौलियों का उन्मूलन 204
काश्तकारी सुधार 205
भूमि के स्वामित्व का पुनर्गठन 207
सहकारी कृषि 209
अभ्यास प्रश्न 210

13 योजना 213

इतिहास 213
बॉम्बे प्लान (बंबई योजना) 213
भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 213

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) 213
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) 214
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) 214
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69) 214
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) 214
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) 214
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) 215
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) 215
दो वार्षिक योजनाएं (1990-92) 215
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) 216
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) 216
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) 216
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) 216
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) 216
योजना के प्रकार 217
एकल स्तरीय बनाम बहुस्तरीय योजना 217
विकेंद्रीकृत योजना 218
जिला योजना समिति 218
महानगर योजना समिति 218
बहुस्तरीय योजना और विकेंद्रीकृत योजना के बीच अंतर 218
योजना की आलोचना 218
आदेशात्मक से सांकेतिक योजना 219
योजना का भविष्य 219
योजना आयोग और नीति आयोग 219
योजना आयोग 219
नीति आयोग 219
योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर 220
अभ्यास प्रश्न 221
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 223

14 औद्योगिक नीति 225

1991 से पहले 225
1948 की औद्योगिक नीति 225
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 226
1991 से पहले की औद्योगिक नीति के पीछे तर्क 226
आलोचना 226

उदारीकरण की दिशा में कदम *227*
आर्थिक सुधार: उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण 227
उदारीकरण *227*
वैश्वीकरण *228*
समाजवादी बनाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 231
समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं *231*
पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं *232*
उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण के बीच संबंध *232*
1991 से औद्योगिक नीति 233
औद्योगिक नीति 1991 के प्रावधान *233*
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए नीति (छोटे उद्योग) *233*
विदेशी निवेश के लिए नीति *234*
सरकार द्वारा विनिवेश *234*
मध्यम, लघु, और सूक्ष्म उद्योग 234
भारत में एमएसएमई का योगदान *236*
चुनौतियां *236*
एमएसएमई पंजीकरण के लाभ *236*
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति: मिश्रित अर्थव्यवस्था 237
वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 237
निजी क्षेत्र का प्रवेश *237*
विशेष आर्थिक क्षेत्र *238*
राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र *239*
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: एक परिचय 240
उच्च विकास की क्षमता *240*
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व *241*
चुनौतियां *241*
मेगा फूड पार्क योजना *242*
सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन *243*
अभ्यास प्रश्न *244*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *247*

15 आधारभूत संरचना **249**

परिवहन 249
विकास का प्रतिरूप *249*
भारत में परिवहन के विकास में समस्याएं *250*

रेलवे 251
रेलवे की लाभप्रदता 251
आजादी के बाद से रेलवे लाइन का विकास 252
रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ 252
क्या रेलवे को निजीकृत किया जाना चाहिए? 253
भारत में रेल लाइन गेज का मुद्दा 253
युनिगेज परियोजना 254
सड़क नेटवर्क 254
राष्ट्रीय राजमार्ग 254
राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें 255
ग्रामीण सड़कें 255
सड़क परिवहन की कमियां 255
बस परिवहन में राज्य सरकार की उपस्थिति 256
भारतीय नौवहन 256
भारतीय नौवहन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं 256
भारत में तटीय नौवहन की स्थिति 257
बंदरगाह 257
नागरिक उड्डयन 258
नागरिक उड्डयन में एफडीआई को 49% तक पेश करने के कारण 258
अंतर्देशीय जलमार्ग 258
विद्युत् 259
ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर उच्च निर्भरता 260
कोयला की गुणवत्ता 260
कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश 261
कच्चा तेल 262
सार्वजनिक निजी साझेदारी 262
अभ्यास प्रश्न 264

16 गैर-निष्पादित संपत्तियां 267

गैर निष्पादित संपत्तियों की परिभाषा 267
एनपीए के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 267
एनपीए की श्रेणियां 268
भारत में एनपीए मुद्दा कितना गंभीर है? 268
उच्च एनपीए के कारण 269
उच्च एनपीए का प्रभाव 269

एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदम 270
ऋण वसूली अधिकरण *270*
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति लाभ प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 *270*
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी *270*
बैड बैंक *271*
ऋण पुनर्गठन *271*
मिशन इंद्रधनुष *271*
बैंक बोर्ड ब्यूरो *272*
एंकर बैंक 272
एसबीआई विलय *272*
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 273
बासल III (बासल समझौते की श्रृंखला का तीसरा चरण) 274
प्रतिभूतिकरण 274
वचन-पत्र और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी 275
पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी *276*
अभ्यास प्रश्न *276*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *278*

17 वित्तीय समावेशन 281

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता 281
वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक शर्तें 281
वित्तीय साक्षरता *281*
वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता *282*
मुद्रा बैंक 282
शरिया/इस्लामिक बैंकिंग 283
इस्लामिक बैंकिंग कैसे काम करती है? *283*
इस्लामिक बैंकिंग का महत्व *284*
भुगतान बैंक 284
एक भुगतान बैंक एक बैंक से कैसे अलग है? *284*
भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन कैसे सुनिश्चित करेंगे? *284*
कौन सी कंपनियों को अनुमोदन दिया गया है? *285*
थोक बैंक 285
लघु वित्त बैंक 286
सार्वभौमिक बैंक 286
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 286

भारत में लोकप्रिय एनबीएफसी *288*
एनबीएफसी के गुण *289*
एनबीएफसी के अवगुण *289*
स्वयं सहायता समूह 290
स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य *290*
सूक्ष्म ऋण 290
भारत में एसएचजी और सूक्ष्म वित्त आंदोलन की स्थिति *290*
भारत में सूक्ष्म वित्त के माध्यम *291*
भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन से संबंधित चिंताएं *291*
आभासी मुद्रा 292
क्रिप्टो करेंसी क्या है? *292*
डिजिटल मुद्रा और आभासी मुद्रा के बीच अंतर *293*
आभासी मुद्रा के लाभ *293*
आभासी मुद्रा के व्यापक उपयोग के संभावित खतरे *294*
प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) *295*
ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी *296*
एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) 298
भीम *299*
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) *299*
अभ्यास प्रश्न *300*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *302*

18 समांतर अर्थव्यवस्था 307

कर नियोजन 307
कर परिहार 307
कर अपवंचन 307
काला बाजार/ चोरबाजार 308
काले बाजारों का समर्थन करने वाले कारक *308*
काला बाजार कीमतें *308*
अलभ्य वस्तु बाजार 308
काली अर्थव्यवस्था (या समांतर अर्थव्यवस्था) 308
धनशोधन/काले धन को वैध बनाना 309
धनशोधन के कुछ सामान्य तरीके *309*
धनशोधन में चुनौतियां *309*
धनशोधन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र *310*
एफएटीएफ सूचियाँ *310*

धनशोधन से निपटने के लिए घरेलू तंत्र *310*
हवाला लेन-देन 312
आधार क्षय एवम् लाभ स्थानांतरण 313
टैक्स हेवन 314
सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम 314
पहली बार गार पर क्यों चर्चा की गई थी? *315*
गार कार्यान्वित करते समय आगे के मुद्दे *315*
शेल कंपनियां 315
अभ्यास प्रश्न *317*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *318*

19 क्षेत्रीय व्यापार समझौता **321**

अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए) 321
मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 321
सीईसीए बनाम सीईपीए *321*
सीमा शुल्क संघ 322
साझा बाजार 322
आर्थिक संघ 322
आर्थिक एकीकरण 323
क्षेत्रीय व्यापार समझौते के प्रभाव 323
उत्पादन पर प्रभाव *323*
खपत पर प्रभाव *324*
भारत पर अन्य देशों के बीच आरटीए जैसे यूरोपीय संघ के प्रभाव 325
भारत को लाभ *325*
चुनौतियां *325*
आरटीए में प्रवेश करने पर भारत के समक्ष समस्याएं 325
आरटीए की सफलता के निर्धारक तत्व 326
क्या आरटीए बहुपक्षीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं? 326
आरटीए बहुपक्षीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं *326*
आरटीए बहुपक्षीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा नहीं देते हैं *326*
अभ्यास प्रश्न *328*

20 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं **331**

टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? 331
सीमाशुल्क 332

सीमाशुल्क के प्रकार *333*
निर्यात शुल्क *334*
पारवहन शुल्क *334*
गैर-टैरिफ बाधाएं 334
परंपरागत बाधाएं *334*
गैर-परंपरागत बाधाएं *334*
अभ्यास प्रश्न *335*

21 भारत की विदेशी मुद्रा दर प्रणाली 337

1947-71 337
ब्रेटन वुड्स समझौते का अंत *338*
1971-75 338
1975-92 338
1992-93 338
1993 के बाद से 339
मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि 340
रुपये में मूल्यह्रास के कारण *340*
रुपये की मूल्य वृद्धि के कारण *341*
रुपये के मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि के प्रभाव *341*
तो कौन सा बेहतर है: मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि? *342*
अवमूल्यन से मूल्यह्रास कैसे अलग है? 342
सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का फैसला कब करती है? *343*
मांग और आपूर्ति की लोच *343*
1966 और 1991 में भारतीय विदेश व्यापार *343*
नाममात्र प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 344
विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप 344
परोक्षत: प्रतिबंधित विनिमय 345
चीन की मुद्रा प्रणाली 345
चीनी मुद्रा का अवमूल्यन *345*
भारत पर यूरोपीय संघ द्वारा समान मुद्रा अपनाने के प्रभाव 345
विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता का संकेतक: आयात आवरण 345
अभ्यास प्रश्न *346*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *348*

22 **परिवर्तनीयता** **351**

चालू खाता परिवर्तनीयता 351
पूंजी खाता परिवर्तनीयता 351
पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के संभावित लाभ *351*
पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के संबंध में चिंताएं *352*
पूंजी खाता परिवर्तनीयता लाने के लिए आवश्यक शर्तें *352*
पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए समिति *352*
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 353
अभ्यास प्रश्न *354*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *355*

23 **भुगतान संतुलन** **357**

चालू खाते के लेनदेन 357
पूंजी खाते के लेनदेन 358
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 364
विदेशी मुद्रा भंडार *365*
विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग 366
संप्रभु धन निधि *366*
अभ्यास प्रश्न *367*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *368*

24 **विदेशी निवेश** **371**

एफडीआई और एफपीआई की नई परिभाषाएं 371
एफडीआई प्रवेश के लिए प्रशासनिक तंत्र 372
स्वचालित मार्ग *372*
अनुमोदन मार्ग *372*
स्वामित्व शेयर के आधार पर विदेशी निवेशक के अधिकार 372
विदेशी निवेश पर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध क्यों हैं? 373
प्रतिबंधित क्षेत्र 376
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कुछ में एफडीआई सीमा का विश्लेषण 376
रक्षा में 100% एफडीआई *376*
खुदरा क्षेत्र में एफडीआई *377*
औषधीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधार *377*

विमान सेवा क्षेत्र में एफडीआई *377*
वैश्विक एफडीआई में भारत का हिस्सा 378
एफडीआई को ग्रहण करने वाले क्षेत्र *379*
राष्ट्रवार भारत के लिए एफडीआई (2015-16) *379*
दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) *379*
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 380
एफपीआई से संबंधित मुद्दे *380*
डिपॉजिटरी रसीद 381
अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद *381*
ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद *381*
भारतीय डिपॉजिटरी रसीद *381*
अभ्यास प्रश्न *382*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *384*

25 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन 387

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 387
आईएमएफ के स्त्रोत *387*
भारत का आईएमएफ के साथ संबंध *388*
आईएमएफ से तकनीकी सहायता *388*
आईएमएफ की भूमिका *388*
आईएमएफ की आलोचना *389*
विश्व बैंक समूह 390
पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) *390*
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) *390*
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) *392*
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) *392*
निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी) *392*
विश्व बैंक की आलोचना *392*
आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट *393*
विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट *393*
व्यापार करने की सुगमता रिपोर्ट *394*
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 395
एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) 395
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) 396
पुनर्वास और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) 396
ईबीआरडी और भारत *397*

सदस्यता के संभावित लाभ *397*
आकस्मिक विदेशी-मुद्रा कोष व्यवस्था (सीआरए) 397
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) 398
अभ्यास प्रश्न *398*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *400*

26 विश्व व्यापार संगठन 403

उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति 403
इतिहास 404
विश्व व्यापार संगठन की गतिविधियां 404
विवाद निपटान 405
विश्व व्यापार संगठन के तहत समझौते 405
वस्तुओं पर समझौता *405*
कृषि उत्पाद पर समझौता (एओए) *406*
सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (गेट्स) 407
बौद्धिक संपदा और ट्रिप्स 408
पेटेंट *409*
भौगोलिक संकेतक *409*
कॉपीराइट *410*
ट्रेडमार्क *411*
व्यापार रहस्य *411*
भारतीय पेटेंट कानून 412
व्यापार संबंधित निवेश उपाय (ट्रिम्स) 415
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 416
महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम *416*
11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, 2017 *417*
व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) 418
सेवा सुविधा समझौता (टीएफएस) 419
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और एओए 419
अभ्यास प्रश्न *420*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *422*

27 भारत की व्यापार नीति 425

1947 से 1970 के दशक के मध्य तक 425
1970 के दशक के मध्य से 1990-91 तक 425

1991 से नीति 426
निर्यात संवर्धन के उपाय 426
निर्यात संवर्धन के लिए उपाय *426*
निर्यात संवर्धन के लिए योजनाएं *427*
विदेशी व्यापार 428
निर्यात *428*
आयात *428*
कच्चा तेल और गैर-तेल आयात *428*
निर्यात और आयात *428*
भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार 430
अभ्यास प्रश्न 430
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *432*

28 विविध विषय **435**

विमुद्रीकरण 435
अपेक्षाएं क्या थीं? *435*
आलोचना *436*
विमुद्रीकरण एक विशाल विफलता क्यों थी? *437*
विमुद्रीकरण : एक कानूनी दृष्टिकोण *437*
2008 का वैश्विक वित्तीय संकट 437
वैश्विक वित्तीय संकट का क्या कारण था? *437*
वैश्विक वित्तीय संकट को खत्म करने के उपाय *438*
यूरोज़ोन संकट 438
यूनानी सरकार द्वारा ऋण चुकौती पर चिंताएं *438*
भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोज़ोन संकट का प्रभाव *439*

समाधान: अभ्यास प्रश्न और पिछली प्रारंभिक परीक्षा **441**
मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति **479**
पिछले वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा) समाधान के साथ **487**
परिशिष्ट I सरकारी योजनाएं **541**
परिशिष्ट II भारतीय अर्थव्यवस्था एक नजर में **631**

प्राक्कथन

आईएएस बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए 'कई' उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात या परिचय हुआ होगा, जो कई वर्षों से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तत्पर हैं और उनकी इसके प्रति प्रतिबद्धता भी निरंतर बनी हुई है। हालांकि, 'कई' शब्द इनकी व्याख्या करने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है। लेकिन जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो हम इसके अर्थ को भलीभांति समझते भी हैं और इसका आदर भी करते हैं। ये युवा पुरुष और महिलाएं इस सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे कीमती युवा वर्षों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ-साथ यह अपनी नींद, आराम और यहां तक कि सामान्य जीवन का त्याग करने को भी तैयार हैं और उनके इस त्याग का केवल एकमात्र लक्ष्य है—**भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।**

अफसोस की बात यह है कि अध्ययन के अंतहीन घंटों और नींद से सराबोर नजरों के बावजूद इन उम्मीदवारों की बड़ी संख्या यह सपना पूरा करने से कोसों दूर है। जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि '**ऐसा क्यों है**', प्रतिक्रियाएं लगभग समान थीं।

"विषय इतना विशाल था कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ था और मैं इसे कभी पूरा नहीं कर सका।."

"मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन उसे याद नहीं रख सका।."

"मैंने पढ़ा कुछ और, लेकिन परीक्षा में पूछा कुछ और गया।."

"मैंने पढ़ना जारी रखा लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने या अभ्यास परीक्षा देने का प्रयास नहीं किया।."

"तैयारी/जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत जैसे कि किताबें, कोचिंग क्लास और इंटरनेट का अनुसरण करना मुश्किल था; आखिर दिन में केवल 24 घंटे होते हैं।"

"मेरी अलमारी बहुत सारी किताबों से भरी हुई थी, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ को ही पूरा कर पाया था।."

ऊपर कहे गए सभी कथनों ने हमें स्पष्ट रूप से एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की, परंतु हमने इसे ना केवल हल करने का प्रयास किया, बल्कि हमने समग्र समाधान पर ध्यान केंद्रित किया, जो थे—विद्वत्ता हासिल करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना।

यह इस उद्देश्य के साथ है कि हमने—PrepMate, Cengage India के साथ मिलकर—एक व्यापक शिक्षण मॉडल विकसित किया है जो प्रिंट और डिजिटल माध्यम का संयोजन है ताकि अधिकांश उम्मीदवारों के उपर्युक्त मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

प्रिंट-डिजिटल मॉडल के बारे में

यह मॉडल यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित अनूठी विशेषताओं के कारण यह पुस्तकें अन्य उपलब्ध पुस्तकों से अलग हैं:

- हम एक वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं, सरल भाषा का उपयोग करते हैं, आरेखों के माध्यम से अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, पर्याप्त उदाहरण उद्धृत करते हैं, एक पाठक अनुकूल प्रारूप में प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं—यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन पुस्तकों को समयबद्ध तरीके से पढ़ा और समेकित किया जा सके।
- हाल ही के वर्षों में यूपीएससी परीक्षाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री विशेष रूप से बनाई गई है। हमने प्रत्येक अध्याय के पश्चात पिछले वर्षों के प्रश्न (समाधान के साथ) भी शामिल किए हैं।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के लिए पर्याप्त हैं।
- पुस्तक श्रृंखला में 'उत्तर कैसे लिखना है' के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी शामिल है जिससे आपका मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दृष्टिकोण विकसित होगा। हमने प्रश्नों को हल करके उत्तर लिखने का ढंग समझाया है और 'श्रेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की शैली' भी सुझाई है।
- हमने एक विशिष्ट विषय पर विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए सभी अध्याय-सामग्री को एक पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है।

आम तौर पर, एक उम्मीदवार एक पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे लेखकों से संपर्क करने का अवसर कभी नहीं मिलता है। हमारा मानना है कि उम्मीदवारों और लेखकों के बीच संपर्क, उम्मीदवारों के विद्वत्ता प्राप्त करने और प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमने आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो आपको आपकी तैयारी के दौरान निरंतर समर्थन प्रदान करता है।

यह इस डिजिटल तत्व के माध्यम से है कि हम निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

1. महत्वपूर्ण और कठिन विषयों पर वीडियो
2. उत्तर लेखन अभ्यास
3. दैनिक प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी
4. साक्षात्कार की तैयारी में सहायता
5. नियमित अद्यतन
6. दैनिक सामयिकी मामले
7. मासिक सामयिकी मामलों पर पत्रिका
8. रेडियो समाचार विश्लेषण
9. शैक्षणिक वीडियो
10. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और समाधान
11. नि: शुल्क अध्ययन सामग्री

आपके सपने को सफल करने की दिशा में हम आपके साथी बनने के लिए तत्पर हैं।

यदि आपका कोई विशिष्ट प्रश्न या रचनात्मक प्रतिक्रिया है, तो आप हमारे साथ info@prepmate.in पर ई-मेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं।

PrepMate

आभार-पूर्ति

“हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह हम एक साथ काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते”

PrepMate द्वारा तैयार किया गया पूरा यूपीएससी मॉडल कई वर्षों का, बहुत से लोगों की लगातार उद्भावना और विचारावेश का परिणाम है। हम ईमानदारी से उनके मूल्यवान योगदान का धन्यवाद करते हैं। मैं, PrepMate Edutech का संस्थापक, शुभम सिंगला, आप सभी का इस पूरी परियोजना में मेरे साथ बने रहने के लिए आभारी हूं। रजिंदर पॉल सिंगला, निर्मल सिंगला, रमनिक जिंदल, शरत गुप्ता, सुभाष सिंगला और विजय सिंगला—आपके निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद।

हम मनींदर मान, सन्दीप सिंह गढ़ा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पहली बार इस मॉडल की कल्पना करने में और फिर इस कल्पना को सहक्रियात्मक प्रिंट-डिजिटल मॉडल का प्रारूप देने में हमारी मदद की—बिना आपके हम अपने प्रतिस्पर्धात्मक आधार को विकसित करने में अक्षम रहते।

रणनीति का कार्यान्वयन अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और डिजिटल घटक का विकास हमारी कल्पना की तुलना में काफी कठिन साबित हुआ। लेकिन हमारी तकनीकी टीम हमारे सपनों को सक्षम करने और सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित थी और उन्होंने निश्चित रूप से इसे पूरा किया। वेबसाइट और एप्लिकेशन दोनों के परीक्षण के लिए एक विशिष्ट उल्लेख के साथ, हम सुरभि मिश्रा, पार्थ और तनवीर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावज़ूद धैर्यपूर्वक और प्रभावी ढंग से अपना कार्य किया।

हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइन टीम, संदीप, सुखजिंदर और रोशनी, की सहायता के बिना हमारी वीडियो और पुस्तकें संभव नहीं हो सकतीं थीं, जिन्होंने बनाए गए ऑडियो-विज़ुअल की सर्वश्रेष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए अंतहीन रूप से कार्य किया।

यह कहना काफी नहीं होगा कि मौज़ूदा विषय सामग्री का उद्गम और निरीक्षण तथा अनुपलब्ध विषय सामग्री की उत्पत्ति, इस परियोजना का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे अध्ययन मॉडल का मूलभूत आधार हैं। विषय सामग्री योगदानकर्ताओं की हमारी टीम के बिना यह संभव नहीं था: ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, गुरदीप कौर, सुरभि मिश्रा, शैफी गर्ग, दीपिका अरोड़ा, सुनील, भूपिंदरजीत सिंह, शांतनु, तनवीर, अनमोल, क्रिती, तान्या, साहिल, सूरज और दिलशाद, जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी—आपके महत्वपूर्ण योगदानों को आभारी रूप से स्वीकार किया जाता है।

हम अपने कर्मचारियों, गीता, जितेंद्र, मनोज और पिंकी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें श्रमशील कार्य का निष्पादन करने में सहायता की, यानी हमारी हस्तलिखित किताबों को टाइप करना-आपके योगदान की ईमानदारी से सराहना की जाती है।

यह अत्यावश्यक है कि हम ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, अंजुम दीवान, राजेश गोयल, शिखा शर्मा और रविंदर इंदौरा को उनकी आलोचनात्मक पर रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए तथा विकास प्रक्रिया के दौरान, बाद में की गई त्रुटियों की पहचान तथा सुधार करने के लिए धन्यवाद दें।

आभार-पूर्ति

हम इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में Cengage India की पूरी संपादकीय टीम द्वारा पहल और समर्थन को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं।

"अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा..."

PrepMate

वीडियो-सूची

1.	प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र कैसे तैयार करें?
2.	आर्थिक गतिविधि के संकेतक (सकल घरेलू उत्पाद और अन्य)
3.	कराधान प्रणाली
4.	वस्तु एवं सेवा कर
5.	मौद्रिक नीति
6.	राजकोषीय नीति
7.	मुद्रास्फीति
8.	भारत की विदेशी मुद्रा दर प्रणाली
9.	भुगतान संतुलन
10.	विश्व व्यापार संगठन

पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण

अध्याय	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	कुल
1. आर्थिक वृद्धि और विकास	4			1		3	1	1	2			**12**
2. भारत की कराधान प्रणाली	1	1		2	1		2	1	1	1		**10**
3. मौद्रिक नीति	1	1	1	2	2	6	2	2	4	1		**22**
4. राजकोषीय नीति	1	1	2		1	1		1	4			**11**
5. मुद्रास्फीति				2	1	3		2	2			**10**
6. भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण				2			2					**4**
7. उपादान	2	1		1					1			**5**
8. आधार	2											**2**
9. वित्तीय बाज़ार	1		1		1				3			**6**
10. जनसंख्या						1	1	1				**3**
11. भारतीय कृषि I: बाज़ार, सिंचाई, और वित्त		1		1		1		1			1	**5**

Contd.

12. भारतीय कृषि II: भूमि सुधार												
13. योजना				1	1				2	2		**6**
14. औद्योगिक नीति	1	1	1				1	3	1			**8**
15. आधारभूत संरचना												
16. गैर-निष्पादित संपत्तियां	2			1				1				**4**
17. वित्तीय समावेशन	2	1	4		1			2	3			**13**
18. समांतर अर्थव्यवस्था			1									**1**
19. क्षेत्रीय व्यापार समझौता												
20. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएँ												
21. भारत की विदेशी मुद्रा दर प्रणाली			1	1		1	1					**4**
22. परिवर्तनीयता				1								**1**

Contd.

23. भुगतान संतुलन					1	2		1				**4**
24. विदेशी निवेश			1				1	1	1			**4**
25. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन			2						2			**4**
26. विश्व व्यापार संगठन	1	2	1	1				1	2	1		**9**
27. भारत की व्यापार नीति			1						1			**2**
परिशिष्ट I- सरकारी योजनाएं	2	11	3	2			3	2	1		2	**26**
कुल	**20**	**20**	**19**	**18**	**9**	**18**	**14**	**20**	**30**	**5**	**3**	**176**

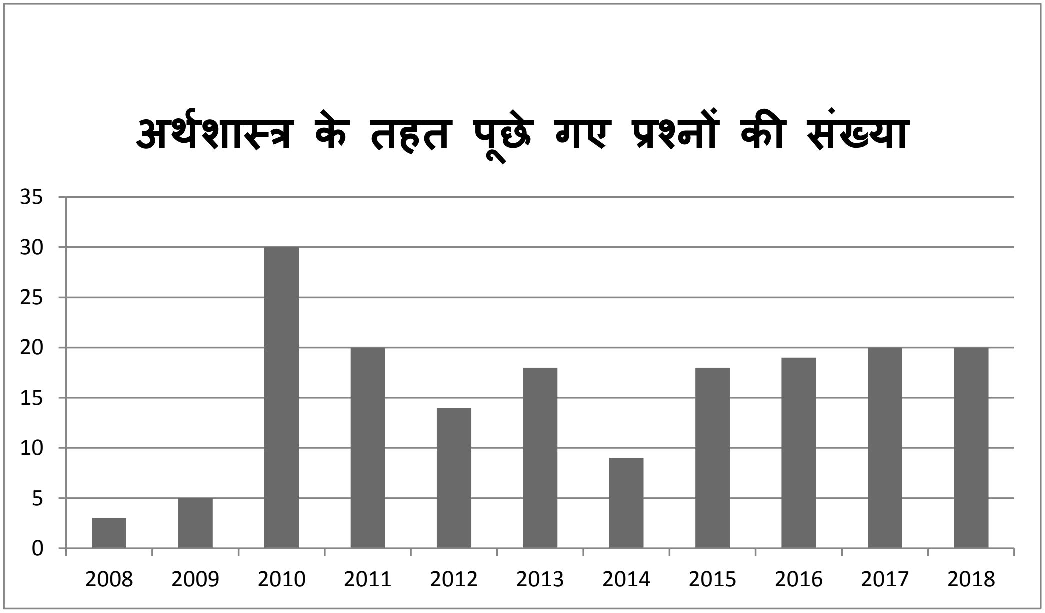

अर्थशास्त्र के तहत पूछे गए प्रश्नों की संख्या
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

अध्याय

1 आर्थिक वृद्धि और विकास

सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product, जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। हालांकि, जीडीपी की गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है, लेकिन इसकी गणना किसी भी समय अवधि के संदर्भ में की जा सकती है।

सकल घरेलू उत्पाद क्या इंगित करता है?

सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग आमतौर पर देश के आर्थिक स्वास्थ्य के संकेतक के साथ-साथ, देश के जीवन स्तर के मूल्यांकन के रूप में किया जाता है।

अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जितना अधिक होगा, लोगों के उपभोग का स्तर उतना ही अधिक होगा। उच्च उपभोग का स्तर लोगों के जीवन स्तर का एक उच्च मानक इंगित करता है।

सकल घरेलू उत्पाद की आलोचना

1. जीडीपी के आलोचकों का तर्क है कि यह उन लेनदेन को ध्यान में नहीं रखता है जो गैरकानूनी हैं और करों से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किए जाते।
2. कुछ आलोचक जीडीपी को कल्याण के संकेतक के रूप में उचित नहीं मानते। वास्तव में, जीडीपी एक राष्ट्र की उत्पादकता के मापक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, लोग अपने आसपास के क्षेत्र में उच्च प्रदूषण के कारण जीवन के उच्च स्तर का आनंद नहीं उठा पाते।

सकल घरेलू उत्पाद की गणना

तीन प्राथमिक तरीकों के आधार पर जीडीपी को निर्धारित किया जा सकता है। सभी तरीकों से जब सही ढंग से गणना की जाती है, तो एक ही तरह के आंकड़े उत्पन्न होते हैं। ये तीन दृष्टिकोण हैं: व्यय दृष्टिकोण, उत्पादन दृष्टिकोण, और आय दृष्टिकोण।

व्यय दृष्टिकोण अंतिम उपभोक्ता द्वारा बिक्री के लिए तैयार उत्पाद विकसित करने में उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों के कुल मूल्य को मापता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक पूर्ण कार का योगदान कार के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत से मापा जाएगा।

उत्पादन दृष्टिकोण व्यय दृष्टिकोण के कुछ विपरीत होता है। आर्थिक गतिविधि में योगदान देने वाली आगत (input) लागतों को विशेष रूप से मापने के बजाय, उत्पादन दृष्टिकोण अंतिम उपभोक्ता द्वारा बिक्री के लिए तैयार उत्पादन के कुल मूल्य का अनुमान लगाता है।

तीसरा दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण, उपर्युक्त दृष्टिकोणों के बीच एक मध्यस्थ है। यह निजी और साथ ही सरकारी क्षेत्रों द्वारा अर्जित सभी घरेलू आय को कुल मिलाकर जीडीपी को मापता है।

भारत का स्थान (फरवरी 2018)

भारत में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office, सीएसओ) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (2.5 ट्रिलियन डॉलर) के आधार पर दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत, क्रम में), और क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) (9.447 ट्रिलियन डॉलर) के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत) अर्थव्यवस्था है।

क्रय शक्ति समानता

क्रय शक्ति समानता (Purchasing Power Parity, पीपीपी) को घरेलू बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की उसी राशि को खरीदने के लिए आवश्यक देश की मुद्रा की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि अमेरिका में 1 डॉलर से खरीदी जाती हैं।

पीपीपी अलग-अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की समान मात्रा खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, यह जानने का प्रयास है। यह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अलग-अलग देशों के बीच अंतर्निहित विनिमय दर (exchange rate) को दर्शाता है, और देशों में वास्तविक जीवन स्तर के अधिक सटीक प्रतिबिंब को दर्शाता है।

अक्सर विनिमय दरें वास्तव में विभिन्न लागतों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं क्योंकि कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, तो दुनिया में कहीं और सस्ता घर मिलना आपके लिए अप्रासंगिक (irrelevant) है। आपके लिए वस्तुओं और सेवाओं की वह कीमत प्रासंगिक है जिस पर आपको वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि डॉलर और रुपया के बीच बाज़ार विनिमय दर 66 है। अमेरिका में एक डॉलर से 1 लीटर दूध खरीदा जाता है। रुपए के मामले में एक डॉलर, यानी 66 रुपये से भारत में 3 लीटर दूध खरीद सकते हैं।

मान लीजिए कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 660 रुपये है। यदि हम बाज़ार विनिमय दर पर विचार करते हैं, तो यह राशि $10 के बराबर है। यदि दूध दुनिया में उत्पादित एकमात्र वस्तु है, कोई सोचता है कि भारत 10 लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है क्योंकि भारत की विनिमय दर 66 रुपये है और सकल घरेलू उत्पाद 660 रुपये है।

हालांकि, भारत 30 लीटर दूध पैदा करता है। इस दोष को दूर करने के लिए, हम क्रय शक्ति समानता विनिमय दर का उपयोग करते हैं। पीपीपी के तहत, हम दोनों देशों में वस्तुओं को खरीदने के लिए आवश्यक धन की तुलना करके भारत के सकल घरेलू उत्पाद को मापते हैं। अमेरिका में $1 से एक लीटर दूध खरीदा जा सकता है, जबकि भारत में 21 रुपये से एक लीटर दूध खरीदा जा सकता है।

$1 = 21 रुपये

इस प्रकार, हमारे उदाहरण में, पीपीपी विनिमय दर 21 रुपये प्रति डॉलर है। इस विनिमय दर का उपयोग करते हुए, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 660 रुपये, $ 30 के बराबर है। इस प्रकार, पीपीपी के आधार पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद $ 30 है। दूसरी तरफ, बाज़ार विनिमय दर के मामले में भारत का सकल घरेलू उत्पाद $ 10 है।

विश्व बैंक (World Bank, डब्ल्यूबी) पीपीपी विनिमय दर की गणना करता है। वर्ष 2014 में विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत के 17.12 रुपये, यूएस $1 के बराबर हैं।

नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर

जब वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है, तो यह नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) प्रदर्शित करता है; जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) के लिए, अनुमान स्थिर मूल्यों पर किया जाता है।

नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा

यह चालू वर्ष की कीमतों पर चालू वर्ष के दौरान उत्पादित आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रास्फीति (inflation) के समायोजन (adjusting) के बिना चालू वर्ष की कीमतों को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है।

वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन × वर्तमान मूल्य = नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा

सकल घरेलू उत्पाद माप स्थिर कीमतों पर किया जाता है, यानी कीमतें जो अतीत में किसी वर्ष के दौरान प्रचलित थी। इन कीमतों को आधार वर्ष (Base year) मूल्य या संदर्भ मूल्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद निरंतर कीमतों पर आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को देश की आर्थिक वृद्धि का एक वास्तविक संकेतक माना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूप में केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की गणना करता है, उनकी बिक्री के मूल्य में वृद्धि की नहीं।

वस्तुओं और सेवाओं का वर्तमान उत्पादन × आधार वर्ष मूल्य = वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गणना करते समय अर्थशास्त्री वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े ध्यान में रखते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

"आर्थिक वृद्धि दर" क्या है?

आर्थिक वृद्धि दर (Economic growth rate) प्रतिशत में एक अवधि से दूसरी अवधि में आर्थिक वृद्धि का एक माप है। व्यावहारिक रूप से, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में हुए परिवर्तन की दर का एक माप है।

आर्थिक वृद्धि दर समग्र अर्थव्यवस्था की सामान्य दिशा और वृद्धि का परिमाण प्रदान करती है। यह एक निश्चित अवधि में किसी देश या अर्थव्यवस्था की आय में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। आमतौर पर, इसकी

तिमाही आधार पर जांच की जाती है, लेकिन आर्थिक वृद्धि दर की गणना बड़ी अवधि के लिए भी की जा सकती है, जैसे साल भर में या दशक में।

आर्थिक वृद्धि आर्थिक उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, लेकिन आर्थिक उत्पादन में परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर एक अर्थव्यवस्था लगातार दो तिमाहियों के लिए जी.डी.पी में गिरावट का अनुभव करती है, तो यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था रिसेशन (Recession) अनुभव कर रही है। अगर अर्थव्यवस्था घटती है (सकल घरेलू उत्पाद कम होता है), तो समय की अवधि के दौरान खोई गई आय का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिशत दर नकारात्मक में व्यक्त की जाती है।

वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर

वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (Real economic growth rate) वास्तविक (नाममात्र पर नहीं) सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से आर्थिक वृद्धि को मापती है । इस प्रकार, वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर में मुद्रास्फीति (Inflation) पहले ही समायोजित होती है।

वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक अवधि से दूसरी में परिवर्तन की दर दिखाती है, आमतौर पर एक वर्ष से अगले वर्ष तक।

वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, जिसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के रूप में भी जाना जाता है, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक उपयोगी है क्योंकि यह केवल उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखती है (और मुद्रास्फीति (मूल्य में वृद्धि) को अनदेखा करती है)।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गणना

उदाहरण के लिए, व्यय दृष्टिकोण से सकल घरेलू उत्पाद की गणना उपभोक्ता व्यय, व्यापार व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात (निर्यात - आयात) के योग के रूप में की जाती है। मुद्रास्फीति को समायोजित करने और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, गणना निम्नानुसार है:

$$\text{वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद} = \frac{\text{सकल घरेलू उत्पाद}}{(1 + \text{आधार वर्ष के बाद से मुद्रास्फीति})}$$

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना हो जाने के बाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की गणना निम्नानुसार की जाती है:

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

$$= \frac{(\text{हाल के वर्ष का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद} - \text{पिछले वर्ष का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद})}{(\text{पिछले साल का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद})} \times 100$$

आधार वर्ष

आधार वर्ष (Base Year) समय-समय पर सरकार द्वारा बदला जाता है। यह एक निर्दिष्ट (designated) वर्ष होता है जो सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, 2011-12

भारत में वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। हाल ही में, सरकार ने आधार वर्ष को 2017-18 में बदलने का प्रस्ताव दिया है।

सकल घरेलू उत्पाद की गणना वर्तमान वर्ष के उत्पादन और आधार वर्ष की कीमतों को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार, जब हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बारे में बात करते हैं, तो हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि स्तर (GDP growth level)

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2017-18 में 6.75 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है और 2018-19 में 7.0 से 7.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, जिससे भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगा। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है।

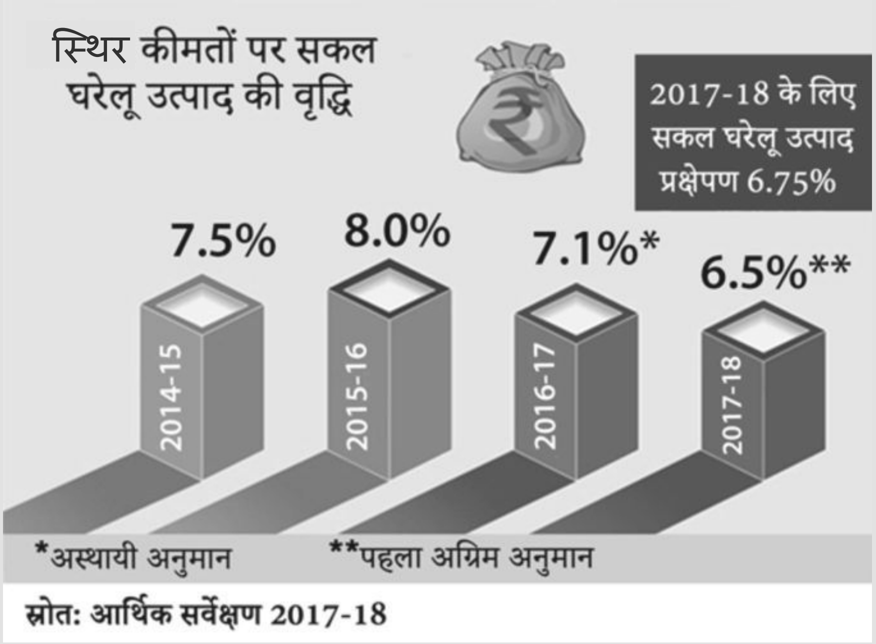

बाज़ार मूल्य और कारक लागत

कारक लागत क्या है?

उत्पादन की प्रक्रिया में कई आगतों (inputs) की आवश्यकता होती है। इन आगतों को आम तौर पर उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है और इनमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं

के उत्पादन के लिए इन कारकों का उपयोग किया जाता हैं। कारक लागत (Factor Cost) वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान एक फर्म द्वारा उपयोग किए गए कारकों की लागत को दर्शाती है। ऐसी कारक लागतों के उदाहरणों में मशीनों का किराया, जमीन का किराया, वेतन और मजदूरी का भुगतान, पूंजी पर ब्याज, और उद्यमी द्वारा कमाया गया मुनाफा (मुनाफा उद्यमी की लागत है) शामिल है।

कारक लागत में सरकार को भुगतान किए गए करों को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि कर उत्पादन प्रक्रिया का भाग नहीं हैं और इसलिए, प्रत्यक्ष उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, प्राप्त उपादान (Subsidy) कारक लागत में शामिल की जाती है क्योंकि उपादान उत्पादन में आगत के उपयोग पर मिलता है।

बाज़ार मूल्य क्या है?

एक बार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाने पर, वह बाज़ार मूल्य पर बेची जाती हैं। बाज़ार मूल्य (Market Price) वह कीमत है जो उपभोक्ता उत्पाद के लिए भुगतान करते हैं, जब वह इसे विक्रेताओं से खरीदते हैं। बाज़ार मूल्य की गणना करने के लिए, कारक लागत में सरकार द्वारा लगाए गए करों को जोड़ा जाता है, जबकि प्रदान की गई उपादान को कारक लागत से घटाया जाता है।

करों को जोड़ा जाता है क्योंकि कर बाज़ार मूल्य में वृद्धि करते हैं। उपादान को घटाया जाता है क्योंकि उपादान कारक लागत की क्षतिपूर्ति करती है या कारक लागत को कम करती है, और इस प्रकार, बाज़ार मूल्य को भी कम करती है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, पैसा उत्पादन का एक कारक है। पैसे की लागत ब्याज है। यहां ब्याज एक कारक लागत है। अगर सरकार ब्याज पर उपादान देती है, तो धन की वास्तविक लागत (ब्याज लागत) कम हो जाएगी।

बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध

सकल घरेलू उत्पाद (बाज़ार मूल्य) - अप्रत्यक्ष कर + उपादान = सकल घरेलू उत्पाद (कारक लागत)

नोट: सामान्य प्रवृत्ति में, जब हम सकल घरेलू उत्पाद शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम बाज़ार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद को संदर्भित करते हैं।

सकल मूल्य संवर्धित या सकल घरेलू उत्पाद (कारक लागत)

सकल मूल्य संवर्धित (Gross Value Added, जीवीए) एक क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है।

सकल घरेलू उत्पाद के साथ संबंध

सकल मूल्य संवर्धित, सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, क्योंकि दोनों उत्पादन के माप हैं। इस संबंध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

सकल मूल्य संवर्धित + उत्पादों पर कर - उत्पादों पर उपादान = सकल घरेलू उत्पाद

सकल मूल्य संवर्धित की गणना क्यों की जाती है?

1. सकल मूल्य संवर्धित और सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः उत्पादकों (आपूर्ति पक्ष) और उपभोक्ताओं (मांग पक्ष) परिप्रेक्ष्य से आर्थिक गतिविधि को मापते हैं, क्योंकि सकल मूल्य संवर्धित उत्पादकों की शुद्ध प्राप्तियाँ (net receipts) हैं और सकल घरेलू उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यय हैं।
2. इन दोनों मापों में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के कारण अंतर होता है (शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर - उपादान)।
3. सकल मूल्य संवर्धित आर्थिक गतिविधि का एक बेहतर माप है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ते कर संग्रह के कारण तेज वृद्धि दर्ज कर सकता है, उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि जरूरी नहीं है।
4. सकल मूल्य संवर्धित आर्थित गतिविधि को बेहतर प्रतिबिंबित करता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं हैं, जो उत्पादित मात्रा के मूल्य को बढ़ा देते हैं।
5. सकल मूल्य संवर्धित माप द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रवार आंकड़े नीति-निर्माताओं को यह तय करने में मदद करते हैं कि किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक माप के रूप में जीवीए का उपयोग?

2015 में यह निर्णय लिया गया कि जीवीए को आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक माप के रूप में अपनाया जाना चाहिए। 2018 में, रिजर्व बैंक वैश्विक प्रथाओं का हवाला देते हुए अपने विकास अनुमानों की पेशकश के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आधारित माप पर वापस आ गया।

वैश्विक प्रवृत्ति क्या है?

वैश्विक स्तर पर, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। यह दृष्टिकोण बहुपक्षीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और निवेशकों के द्वारा अपनाया जाता है। मुख्य रूप से वे सभी जीडीपी आंकड़ों का उपयोग करते हैं क्योंकि यह आसानी से देशों की तुलना की सुविधा प्रदान करते हैं।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product, जीएनपी) भारत या विदेश में भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है?

जीएनपी = सकल घरेलू उत्पाद - भारत में विदेशियों द्वारा उत्पादन + भारत के बाहर भारतीयों द्वारा उत्पादन

या

जीएनपी = जीडीपी - भारत में विदेशियों को भुगतान की गई कारक आय + विदेश में भारतीयों को भुगतान की गई कारक आय

यानी,

जीएनपी = जीडीपी - विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय

जीएनपी एक निश्चित समय अवधि में दुनिया में कहीं भी नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है।

सकल घरेलू उत्पाद के साथ तुलना

सकल घरेलू उत्पाद भारत जैसे क्षेत्र में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जबकि जीएनपी भारतीयों जैसे नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

भारत में, सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य जीएनपी की तुलना में अधिक है क्योंकि विदेश में भारतीयों द्वारा किए गए निवेश की तुलना में भारत को विदेश से अधिक निवेश प्राप्त हुआ है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (बाज़ार मूल्य पर)

जब भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियों की खपत होती है (या उनके मूल्य में कमी आती है); संपत्तियों की इस खपत (या मूल्य में कमी) को मूल्यह्रास (depreciation) कहा जाता है।

हम एनडीपी (Net Domestic Product) की गणना कैसे करते हैं?

जब भी हम सकल मूल्य से शुद्ध मूल्य की गणना करते हैं, हम सकल मूल्य से मूल्यह्रास घटाते हैं।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) = जीडीपी - मूल्यह्रास

राष्ट्रीय आय या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

राष्ट्रीय आय या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (National Income or Net National Product at Factor Cost) एक निर्दिष्ट समय अवधि में नागरिकों (जैसे भारतीयों) द्वारा अर्जित आय है।

दूसरे शब्दों में, यह किसी दिए गए समयावधि में नागरिकों की सामूहिक आय है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद - मूल्यह्रास - अप्रत्यक्ष कर + उपादान

या

कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद - विदेश से शुद्ध कारक आय - मूल्यह्रास - अप्रत्यक्ष कर + उपादान

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय या औसत आय (Per Capita Income) निर्दिष्ट वर्ष में किसी दिए गए क्षेत्र (शहर, क्षेत्र, देश इत्यादि) में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय को मापती है। क्षेत्र की कुल आय को कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित करके इसकी गणना की जाती है।

दूसरे शब्दों में, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए एक राष्ट्रीय आय को देश की आबादी से विभाजित किया जाता है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{आबादी}}$$

2015-16 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 93,293 रुपये थी, जो पिछले वर्ष में 88,879 रुपये थी।

वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से, 2015-16 के दौरान प्रति व्यक्ति आय (2011-12 की कीमतों पर) 74,435 रुपये थी तथा 2014-15 के दौरान 72,889 रुपये थी। इस प्रकार, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 6.2% की वृद्धि हुई है।

नाममात्र प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति समायोजित करने के बाद वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है।

$$\text{वास्तविक प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{नाममात्र प्रति व्यक्ति आय}}{1 + \text{मुद्रास्फीति दर}}$$

आइए निम्नलिखित तालिका में दिए गए वास्तविक आंकड़ों के साथ उपरोक्त अवधारणाओं को समझें:

(₹ 1000 करोड़)

वर्ष (Year)	स्थायी पूंजी की खपत (मूल्यह्रास) (Consumption of fixed cap. (depreciation))	अप्रत्यक्ष कर-उपादान (Indirect taxes less subsides)	बाज़ार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at market prices)	बाज़ार की कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP at market prices)	विदेश से शुद्ध कारक आय (Net factor income from abroad)	कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNP at factor cost or net national income)	प्रति व्यक्ति आय (₹) (Per capita income (₹)
2015-16	1278	923	11350	10072	–137	9012	77,435
2014-15	1193	825	10552	9359	–124	8410	72,889
2013-14	1102	755	9839	8737	–122	7860	68,867

बाज़ार की कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद = बाज़ार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद - मूल्यह्रास

कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = बाज़ार की कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद - अप्रत्यक्ष कर कम उपादान - विदेश से शुद्ध कारक आय

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद}}{\text{आबादी}}$$

आर्थिक वृद्धि का बेहतर माप कौन सा है: सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय?

आर्थिक वृद्धि जीडीपी के विस्तार के आधार पर मापी जाती है। हालांकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जब जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी में वृद्धि की दर से अधिक होती है। ऐसे मामलों में, जीडीपी बढ़ती है परंतु प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इसलिए, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक वृद्धि का एक बेहतर संकेतक माना जाता है क्योंकि यह जनसंख्या के आंकड़ों को भी ध्यान में रखता है।

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 8-9% बढ़ सकती है?

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के चरण से गुज़र रही है। हालांकि, 2005-06 की शुरुआत से 9 साल की अवधि में, औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.7% थी। इस पृष्ठभूमि के आधार पर, प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर 8-9% प्रतिवर्ष वृद्धि करने की क्षमता रखती है या नहीं।

पिछला प्रदर्शन

2005-06 में भारत ने 9.5% की वृद्धि दर हासिल की, इसके बाद 2 वर्षों में 9.6% और 9.3% की वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के चलते थोड़ी सी गिरावट के बाद, 2010-11 में वृद्धि दर 8.9% तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान घरेलू बचत दर (Savings rate) जीडीपी का 34.9% औसत था। इसी प्रकार, सकल पूंजी निर्माण दर (Gross Capital Formation rate) औसत 36.2% था।

वृद्धि दर में कमी के कारण: कम निवेश और उच्च वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात

2012-13 के बाद की अवधि के आंकड़ों का एक विश्लेषण दो रुझान बताता है। सबसे पहले, निवेश दर में गिरावट आई है। दूसरा, वृद्धि दर में गिरावट निवेश दर में गिरावट से अधिक है, जो वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (Incremental Capital- Output Ratio, आईसीओआर) में वृद्धि दर्शाती है। 2007-08 में, भारत की निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद की 38% थी। 2012-13 में निवेश दर 34.8% थी। 2015-16 में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।

4 वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) के साथ, केवल उच्च स्तर की बचत और निवेश दर पर 8-9% वृद्धि दर पर वापस पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार, "उच्च वृद्धि दर" हासिल करने के लिए निवेश दर बढ़ाने और पूंजी की उत्पादकता (आईसीओआर) में सुधार करना आवश्यक है।

वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात

वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात रुपये 1 से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी में जोड़ को संदर्भित करता है। आईसीओआर जितना अधिक होगा, पूंजी की उत्पादकता उतनी ही कम होगी।

$$\text{आईसीओआर} = \frac{\text{वृद्धिशील पूंजी रुपये 1 से उत्पादन बढ़ाने के लिए}}{\text{उत्पादन में 1 रुपये से वृद्धि (1)}}$$

इस प्रकार, एक उच्च आईसीओआर पूंजी का अक्षम प्रयोग दर्शाता है। अधिकांश देशों में, आईसीओआर 3 के करीब है। भारत में, आईसीओआर लगभग 4 है। विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में आईसीओआर सेवा उद्योग में कम होता है।

आईसीओआर प्रौद्योगिकी, श्रम बल के कौशल जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है, जो बदले में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और व्यवसाय करने में आसानी आदि पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा नौकरशाही बाधाएं, जो परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन में बाधा डालती हैं, को हटाने की जरूरत है। इस प्रकार, पूंजी की उत्पादकता में सुधार के लिए कई मोर्चों पर कदमों की आवश्यकता है।

"बचत दर" क्या है?

आय से सभी खर्चों के बाद जो बचता है, उसे बचत कहते हैं। बचत दर (Savings Rate) की गणना करने के लिए बचत को आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गणना व्यक्ति, क्षेत्र, अर्थव्यवस्था आदि स्तर पर की जा सकती है।

$$\text{बचत दर} = \frac{\text{बचत}}{\text{आय}} \times 100$$

$$\text{दूसरे शब्दों में, भारत का बचत दर} = \frac{\text{भारत में कुल बचत}}{\text{जीडीपी}} \times 100$$

"बचत दर" का वैश्विक रुझान

पिछले वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बचत दर में कमी आई है। 1970 और 1980 के दशक में, व्यक्तिगत बचत दर 5-7% की सीमा में थी लेकिन 21वीं शताब्दी में 1-3% की सीमा में थी।

इसकी तुलना में, चीन और भारत में बचत दर लगभग 30% है। भारत का घरेलू बचत दर 2007 में 38.3 प्रतिशत की चोटी से घटकर 2013 में 29.2 प्रतिशत हो गया, जो 2016 में 29 प्रतिशत रह गया था। 2007 से 2016 तक, बचत दर की तुलना में निवेश दर में अधिक गिरावट आई है। भारत में, निवेश दर में कमी 2012 में शुरू हुई, यह कमी तीव्रता से बड़ी और स्पष्ट रूप से 2016 के आंकड़ों के अनुसार जारी है।

बचत दर को क्या प्रभावित करता है?

राष्ट्रीय औसत बचत दर अक्सर इस पर आधारित होती है कि विशेष संस्कृति ऋण (ऋण), संपत्ति, आदि की तरफ कैसा दृष्टिकोण रखती है। उपभोग की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर कम होती है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जो निवेश की ओर उन्मुख है, में बचत उच्च दर है। आय के स्तर में वृद्धि से भी बचत दर प्रभावित होता है।

निवेश दर

निवेश दर (Investment Rate) की गणना करने के लिए निवेश को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च बचत दर अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश दर की ओर ले जाती है।

आर्थिक वृद्धि निवेश दर और आईसीओआर पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक वृद्धि = निवेश दर × 1/आईसीओआर

आइए मान लें कि निवेश दर 32% है और आईसीओआर 4 है। परिणामस्वरूप, आर्थिक वृद्धि = 32% × (1/4) = 8% होगी।

आर्थिक विकास की परिभाषा

मात्रात्मक लक्ष्यों जैसे सकल घरेलू उत्पाद के स्तर में वृद्धि पर अधिक जोर देने के कारण तथा राष्ट्रों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता जैसे गैर- मात्रात्मक मानकों को अनदेखा करने के कारण आर्थिक विकास की अवधारणा का जन्म हुआ।

आर्थिक विकास को उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में सुधार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है।

“आर्थिक वृद्धि” और “आर्थिक विकास” को समझने के लिए, हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेंगे। शब्द “मनुष्यों की वृद्धि” का अर्थ केवल उनकी ऊंचाई और वजन में वृद्धि है, जो पूरी तरह मात्रात्मक हैं। लेकिन यदि आप “मानव विकास” के बारे में बात करते हैं, तो यह परिपक्वता स्तर, दृष्टिकोण, आदतों, व्यवहार, भावनाओं, बुद्धि, आदि जैसे गैर- मात्रात्मक पहलुओं पर निर्भर करता है।

इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को वृद्धि दर के माध्यम से मापा जा सकता है; लेकिन आर्थिक विकास में न केवल मात्रात्मक बल्कि गैर- मात्रात्मक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि निवासियों की जीवनशैली में सुधार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में सुधार इत्यादि।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि शामिल है। भारत के संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि भारत तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है लेकिन आर्थिक विकास धीमी गति से हो रहा है।

आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच महत्वपूर्ण अंतर

आर्थिक वृद्धि और विकास के बीच मौलिक अंतर निम्नलिखित बिंदुओं में समझाए गए हैं:

1. आर्थिक वृद्धि समय की एक विशेष अवधि में देश के वास्तविक उत्पादन में सकारात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, जीवन स्तर में सुधार आदि के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि शामिल है।
2. आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। हालांकि, आर्थिक विकास के लिए यह एकमात्र आवश्यकता नहीं है।
3. आर्थिक वृद्धि जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि जैसे संकेतकों में वृद्धि को सक्षम बनाता है। दूसरी तरफ, आर्थिक विकास जीवन प्रत्याशा दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और गरीबी दर में सुधार को सक्षम बनाता है।
4. आर्थिक वृद्धि से मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, लेकिन आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों लाता है।
5. आर्थिक वृद्धि को एक विशेष अवधि के लिए मापा जा सकता है। दूसरी तरफ, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे लंबे समय तक देखा जा सकता है।

समावेशी वृद्धि

समावेशी वृद्धि (Inclusive Growth) वह आर्थिक वृद्धि है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करती है। समावेशी वृद्धि मूल रूप से यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वर्ग को आर्थिक वृद्धि से लाभ हो, उनकी आर्थिक दशा, लिंग, अक्षमता, धर्म, आदि के बावजूद।

समावेशी वृद्धि दृष्टिकोण दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर है; गरीब लोगों के बीच केवल आय पुनर्वितरण की बजाय रोजगार उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उदारीकरण के साथ, आर्थिक वृद्धि के लाभ समृद्ध और मध्यम वर्ग जैसे कुछ वर्गों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। गरीबों पर आर्थिक वृद्धि का असर कम रहा है। नतीजतन, समावेशी वृद्धि पर जोर देना आवश्यक है।

समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के दृष्टिकोण

रिस रिसकर लाभ नीचे पहुंचने का सिद्धांत (Trickle down approach)

रिस रिसकर लाभ नीचे पहुंचने का सिद्धांत (Trickle down approach) का प्रयोग इस विश्वास के आधार पर किया जाता है कि यदि उच्च आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, तो उनकी बढ़ी आय और धन समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अधिक कमाता है, तो वह अधिक खर्च करता है। उसके द्वारा किया गया खर्च अन्य व्यक्तियों की आय है।

सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला

समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रिस रिसकर लाभ नीचे पहुंचने का सिद्धांत पूरी तरह सफल नहीं रहा है। आर्थिक वृद्धि ने समाज के गरीब वर्गों को नजरअंदाज कर दिया है। सरकार ने समाज के विशेष रूप से गरीब वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। यह दृष्टिकोण समावेशी विकास लाने के लिए अधिक प्रभावी है क्योंकि यह विशेष रूप से गरीब वर्गों की तरफ लक्षित है।

लोरेंज वक्र

लोरेंज वक्र (Lorenz Curve) 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लोरेंज द्वारा विकसित किया गया था। लोरेंज वक्र धन वितरण को चित्रात्मक (ग्राफिकल) रूप में दर्शाता है। ग्राफ पर, सीधी विकर्ण रेखा धन वितरण की पूर्ण समानता को दर्शाती है; लोरेंज वक्र इसके नीचे बनता है, किसी अर्थव्यवस्था में धन वितरण की वास्तविकता दर्शाता है। सीधी विकर्ण रेखा और लोरेंज वक्र (घुमावदार रेखा) के बीच का अंतर धन वितरण की असमानता की मात्रा को दर्शाता है।

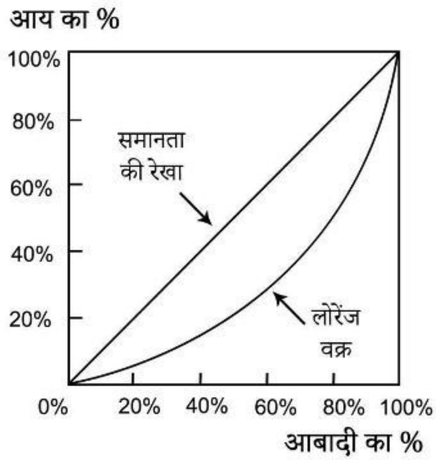

गिनी गुणांक

गिनी गुणांक (Gini Coefficient) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

$$\text{गिनी गुणांक} = \frac{\text{समानता रेखा और लोरेंज वक्र के बीच क्षेत्र}}{\text{समानता रेखा के तहत क्षेत्र}}$$

गिनी गुणांक का मूल्य 0 से 1 तक है। गिनी गुणांक राष्ट्रों में धन वितरण के रुझान का प्रदर्शन करता है।

लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक, और असमानता माप

एक अर्थव्यवस्था जिसमें पूर्ण समानता होती है, 20% जनसंख्या के पास 20% धन होगा। जनसंख्या और संपत्ति का अनुपात हमेशा एक के बराबर होता है।

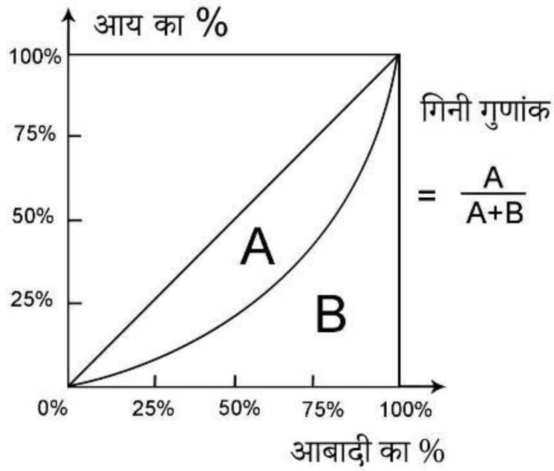

एक पूर्ण असमानता वक्र का गिनी गुणांक 1 होता है, और इसका मतलब होता है कि पूरे देश की संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास है।

एक राष्ट्र के भीतर जितनी अधिक आर्थिक असमानता होती है, गिनी गुणांक उतना ही 1 की ओर होगा। 2011 में भारत का गिनी गुणांक 0.35 था।

आर्थिक गतिविधि के स्तर से संबंधित शब्दावली

1. धीमी **अर्थव्यवस्था (स्लो-डाउन, Slow down):** यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8% से 5% हो गई है। धीमी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लेकिन कम दर पर।
2. **रिसेसन या मंदी (Recession):** यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था आकार में कम हो रही है। पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि मंदी का मतलब कम से कम दो तिमाहियों के लिए नकारात्मक वृद्धि दर है।
3. **अर्थव्यवस्था का विस्तार (Expansion of the economy):** यह अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि का संकेत देता है। दूसरे शब्दों में, विस्तार अर्थव्यवस्था के सकारात्मक वृद्धि दर को संदर्भित करता है। अर्थव्यवस्था धीमी और विस्तार एक ही समय में हो सकती है।
4. **उछाल (Boom):** अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में वृद्धि को उछाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5% से बढ़कर 8% हो गई है। उछाल के मामले में, अर्थव्यवस्था उस दर से तेज बढ़ती है जिस पर यह पहले बढ़ रही थी।
5. **मेल्टडाउन (Meltdown):** एक ऐसी स्थिति जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था अचानक बुरे वक्त का अनुभव करती है। ऐसी स्थिति में अक्सर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कम हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिर जाती हैं, नकद तरलता लगभग सूख जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती-घटती हैं, आदि।

भारत में गरीबी अनुमान

1993 में, योजना आयोग ने लकड़वाला की अध्यक्षता में भारत में गरीबी अनुमानों की गणना के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

1. कैलोरी सेवन के आधार पर उपभोग व्यय की गणना की जानी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी।
2. राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके, किया जाना चाहिए।

तेंदुलकर समिति, 2005 (सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में)

गरीबी की गणना के पिछले तरीकों में तीन कमियों को संबोधित करने के लिए योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति गठित की गई थी:

1. उपभोग व्यय 1973-74 के उपभोग प्रतिरूप पर आधारित थे। हालांकि, 1 973-74 के बाद उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसलिए, तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय निर्धारित करने के लिए उपभोग के वर्तमान प्रतिरूप का उपयोग किया।
2. इससे पहले, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय को नजरअंदाज कर दिया गया था। तेंदुलकर समिति ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय को मान्यता दी। गरीब बच्चों की शिक्षा पर व्यय राज्य द्वारा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, गरीब जनता द्वारा शिक्षा के लिए कोई व्यय नहीं किया जाता।

   स्वास्थ्य पर व्यय की गणना करने के लिए, प्रतिवर्ष 30 रुपये का व्यय जोड़ा गया जो कि 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
3. इससे पहले, गरीबी अनुमान समान संदर्भ अवधि पर आधारित थे, यानी उत्तरदाताओं को पिछले 30 दिनों में उनके द्वारा किए गए व्यय का विस्तार करने के लिए कहा जाता था। जबकि मिश्रित संदर्भ अवधि विधि के तहत, कपड़े, जूते, टिकाऊ, शिक्षा व्यय, और स्वास्थ्य व्यय जैसी पांच कम आवृत्ति वस्तुओं का सर्वेक्षण पिछले 365 दिनों के लिए और अन्य सभी वस्तुओं का सर्वेक्षण पिछले 30 दिनों के लिए किया जाता है।

2011-12 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे 25.7% ग्रामीण आबादी, 13.7% शहरी आबादी और 21.9% समग्र आबादी थी।

रंगाराजन समिति

2012 में, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए योजना आयोग ने रंगाराजन समिति की स्थापना की थी। नई समिति ने गरीबी अनुमान पद्धति में और सुधारों का सुझाव दिया।

तेंदुलकर	रंगाराजन
केवल भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ों पर व्यय की गणना करती है।	भोजन + गैर-खाद्य पदार्थ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, परिवहन (परिवहन), किराया
	• ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी तेज दर से बढ़ रही है। • यह स्पष्ट है, क्योंकि रंगाराजन ने किराया, शिक्षा इत्यादि जैसी गैर-खाद्य वस्तुएं को ज्यादा अहमियत दी। • गांवों की तुलना में, शहरों में ये वस्तुएं/सेवाएं अधिक महंगी हैं।
	रंगाराजन ने सिफारिश की कि किसी भी समय, निचले आर्थिक स्तर के 35% ग्रामीण लोगों और 25% शहरी लोगों को गरीब माना जाना चाहिए।
	• सरकारी योजनाओं के तहत हकदारता से गरीबी अनुपात को अलग किया जाना चाहिए। • उदाहरण के लिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते खाद्यान्न गरीबी रेखा मानदंडों के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक जाति जनगणना के आधार पर दिए जाने चाहिए।

बेरोजगारी

बेरोजगारी (Unemployment) तब होती है जब एक व्यक्ति जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है, वह काम खोजने में असमर्थ है। बेरोजगारी दर अक्सर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के माप के रूप में प्रयोग की जाती है। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार लोगों की संख्या से श्रम बल की कुल संख्या को विभाजित करके की जाती है।

जबकि बेरोजगारी की परिभाषा स्पष्ट है, अर्थशास्त्री कई अलग-अलग श्रेणियों में बेरोजगारी को बांटते हैं।

बेरोजगारी के प्रकार

असंतुलनात्मक बेरोजगारी (Disequilibrium unemployment): संतुलन स्तर पर, मजदूरी दर ऐसी होती है कि श्रम की मांग श्रम की आपूर्ति के साथ मेल खाती है।

जब सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की जाती है या ट्रेड यूनियनों के हस्तक्षेप के कारण मजदूरी दर संतुलन स्तर से ज्यादा की जाती है, तो श्रम की मांग कम हो जाती है और श्रम की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच विसंगति की स्थिति पैदा होती है।

इस प्रकार की बेरोजगारी को शास्त्रीय (क्लासिकल) या वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी भी कहा जाता है।

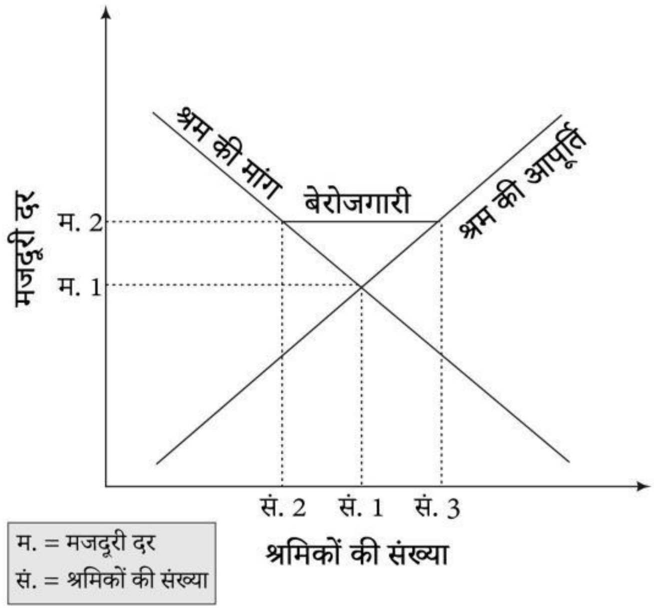

प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर्षण बेरोजगारी (Frictional unemployment): घर्षण बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो नौकरियों के बीच बिताए गए समय से होती है, जब एक कर्मचारी एक नौकरी छोड़ कर दूसरे नौकरी की खोज कर रहा हो या एक नौकरी से दूसरी नौकरी में संक्रमण कर रहा हो। इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment): संरचनात्मक बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलावों के कारण बेरोजगारी का एक दीर्घकालिक रूप है। अक्सर प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीति जैसे कारक इस तरह की बेरोजगारी में वृद्धि करते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कई कारणों से हो सकती है- श्रमिकों में अपेक्षित कौशल की कमी या मजदूर उन क्षेत्रों से बहुत दूर रहते हैं जहां नौकरियां उपलब्ध हैं और करीब नहीं जा सकते हैं। इस तरह की बेरोजगारी के दौरान नौकरियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन नियोक्ता की ज़रूरत और कर्मचारियों की पेशकश में गंभीर अंतर होता है।

चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical unemployment): चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र के कारण होती है। मंदी की अवधि के दौरान चक्रीय बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास की अवधि के दौरान बेरोजगारी में गिरावट आती है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal unemployment): यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो साल में कुछ समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए, मनोरंजन पार्क मौसमी बेरोजगारी का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों के महीनों के दौरान कम लोग इन पार्कों में जाते हैं।

प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी (Disguised unemployment): छिपी बेरोजगारी वहाँ मौजूद होती है जहां श्रम बल का हिस्सा या तो काम के बिना है या अनावश्यक तरीके से काम कर रहा है। इस प्रकार श्रम की सीमांत उत्पादकता (marginal productivity) शून्य होती है।

दूसरे शब्दों में, छिपी बेरोजगारी एक तरह की बेरोजगारी है जिसमें कुछ लोग पूरी तरह से नियोजित नहीं होते हैं। भारतीय कृषि में छिपी बेरोजगारी अधिक है।

अल्प रोज़गार (Underemployment): एक ऐसी स्थिति जिसमें एक कर्मचारी नियोजित होता है लेकिन वांछित क्षमता पर नहीं, चाहे मुआवजे, घंटों, कौशल और अनुभव स्तर के मामले में। अल्प रोज़गार श्रमिक अक्सर असंतुष्ट होते हैं और उपयुक्त नौकरी की तलाश जारी रखते हैं।

फिलिप्स वक्र

फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) ए डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है। इस वक्र से पता चलता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और उलटा संबंध है। सिद्धांत बताता है कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के साथ होती है, जिसके परिणाम स्वरुप अधिक रोजगार और कम बेरोजगारी होती है।

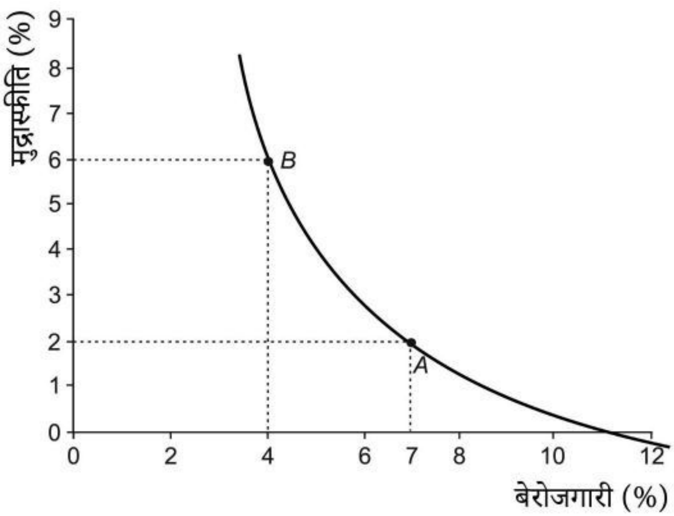

हालांकि, मूल अवधारणा को कुछ हद तक अवरुद्धतामय स्फीति की घटना के कारण अस्वीकार करा जाता है; अवरुद्धतामय स्फीति में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों के उच्च स्तर होते हैं।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अवसरों की संख्या और स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।

मानव विकास की वर्तमान अवधारणा, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ महबूब उल हक ने पेश की थी। उनके अनुसार, मानव विकास लोगों के पास विकल्पों में वृद्धि को संदर्भित करता है। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी मानव विकास के इस दृष्टिकोण को अपनाया है।

लोगों के पास विकल्पों को या तो लोगों के कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके), उनके स्वास्थ्य में सुधार, या उनके आय स्तर में वृद्धि द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा लोगों के पास विकल्पों को बढ़ाती है क्योंकि शिक्षा उन्हें विभिन्न व्यवसाय विकल्पों में से चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। स्वास्थ्य लोगों के पास विकल्पों को बढ़ाता है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक रोगी की

तुलना में, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर सकता है। आय स्तर में वृद्धि विकल्पों को बढ़ाती है क्योंकि यह लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाती है।

मानव विकास सूचकांक

उपरोक्त विचार के आधार पर, मानव विकास सूचकांक (Human Development Index, एचडीआई) महबूब उल हक द्वारा अमर्त्य सेन के साथ विकसित किया गया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रक्षेपण किया गया था।

मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए नई विधि

अपनी 2010 मानव विकास रिपोर्ट में, यूएनडीपी ने एचडीआई की गणना के लिए एक नई विधि का उपयोग किया था। एचडीआई की गणना के लिए निम्नलिखित तीन सूचकांक का उपयोग किया जाता है:

1. **एक लंबा और स्वस्थ जीवन (Life longetivity):** जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा।
2. **शिक्षा सूचकांक (Education index):** शिक्षा के औसत वर्ष और शिक्षा के अपेक्षित वर्ष।
3. **जीवन स्तर (Standard of living):** प्रति व्यक्ति आय (यूएस $ पीपीपी)।

जीवन प्रत्याशा सूचकांक (Life Expectancy Index)

जीवन प्रत्याशा सूचकांक 1 है, जब जन्म पर जीवन प्रत्याशा 85 होती है; और 0 है, जब जन्म पर जीवन प्रत्याशा 20 होती है।

$$\text{जीवन प्रत्याशा सूचकांक} = \frac{\text{जीवन प्रत्याशा} - 20}{85 - 20}$$

जीवन प्रत्याशा: किसी दिए गए देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

शिक्षा सूचकांक (Education Index)

$$\text{शिक्षा सूचकांक} = \frac{\text{शिक्षा के औसत वर्ष सूचकांक} + \text{शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सूचकांक}}{2}$$

- $\text{शिक्षा के औसत वर्ष सूचकांक} = \frac{\text{शिक्षा के औसत वर्ष}}{15}$

  पंद्रह शिक्षा के अधिकतम वर्ष हैं।

  शिक्षा के औसत वर्ष: यानी साल, जो 25 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति ने औपचारिक शिक्षा में बिताए

- $\text{शिक्षा के अपेक्षित वर्ष सूचकांक} = \frac{\text{शिक्षा के अपेक्षित वर्ष}}{18}$

अठारह अधिकांश देशों में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के बराबर है।

शिक्षा के अपेक्षित वर्ष: यानी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के कुल अपेक्षित वर्ष

आय सूचकांक (Income Index)

आय सूचकांक 1 है, जब सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति $ 75,000 प्रति वर्ष होती है और 0 है, जब सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति $ 100 प्रति वर्ष होती है।

$$\text{आय सूचकांक} = \frac{\text{सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति} - 100}{75000 - 100}$$

मानव विकास सूचकांक का मूल्य

मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मूल्य (Value of HDI) 1 हो सकता है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, और आय सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है।

$$\text{मानव विकास सूचकांक} = \sqrt[3]{\text{जीवन प्रत्याशा सूचकांक} \times \text{शिक्षा सूचकांक} \times \text{आय सूचकांक}}$$

मानव विकास के विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रों का वर्गीकरण

मानव विकास का स्तर	उच्च (0.7 और ऊपर)	मध्यम (0.55 से 0.6 99)	कम (0 से .549)
राष्ट्र	उत्तरी अमेरिका, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप	दक्षिण अमेरिका और एशिया	अफ्रीका
आर्थिक विकास अवस्था	विकसित	विकासशील	अविकसित
राजनीतिक स्थिति	राजनीतिक स्थिरता	अस्थिरता का इतिहास लेकिन वर्तमान में स्थिर राष्ट्र	गृहयुद्ध से गुजर रहे राष्ट्र

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index, एमपीआई) 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एंव मानव विकास नेतृत्व (Oxford Poverty and Human Development Initiative) और यूएनडीपी द्वारा विकसित

किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने पहले उपयोग किए जाने वाले मानव गरीबी सूचकांक को प्रतिस्थापित कर दिया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करता है। सूचकांक मानव विकास सूचकांक के समान तीन आयामों का उपयोग करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर। तीन आयामों को 10 संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है। यह आय आधारित माप के साथ; शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के संबंध में गंभीर वंचितताओं के आधार पर गरीबी मापता है।

आयाम (Dimension)	**संकेतक (Indicators)**
स्वास्थ्य	• बाल मृत्यु दर • पोषण
शिक्षा	• स्कूली शिक्षा के वर्ष • विद्यालय उपस्थिति
जीवन स्तर	• खाना पकाने का ईंधन • शौचालय • पानी • बिजली • घर का फर्श • संपत्ति

संकेतक

निम्नलिखित 10 संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं:

शिक्षा (प्रत्येक सूचक को 1/6 पर समान रूप से भारित किया जाता है)

1. **स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of schooling):** वंचित अगर कोई घरेलू सदस्य 6 साल की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है
2. **बाल की विद्यालय उपस्थिति (Child school attendance):** वंचित अगर कोई भी स्कूल आयु वर्ग का बच्चा कक्षा 8 तक स्कूल में नहीं जा रहा

स्वास्थ्य (प्रत्येक सूचक को 1/6 पर समान रूप से भारित किया जाता है)

3. **बाल मृत्यु दर (Child mortality):** वंचित अगर पिछले 5 सालों में परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई है
4. **पोषण (Nutrition):** वंचित अगर कोई वयस्क या बच्चा छोटे कद का है

जीवन स्तर (प्रत्येक सूचक को 1/18 पर समान रूप से भारित किया जाता है)

5. **बिजली (Electricity):** वंचित अगर घर में बिजली नहीं है
6. **स्वच्छता (Sanitation):** वंचित अगर घर की स्वच्छता सुविधा में सुधार नहीं हुआ है (सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals, एमडीजी) दिशानिर्देशों के अनुसार), या यह बेहतर है लेकिन अन्य घरों के साथ साझा किया जाता है
7. **पीने का पानी (Drinking water):** वंचित अगर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है (एमडीजी दिशानिर्देशों के अनुसार) या सुरक्षित पेयजल घर से 30 मिनट की पैदल दूरी (आना और जाना मिलाकर) से अधिक है
8. **घर का फर्श (Floor):** वंचित अगर घर में रेत या गोबर का फर्श होता है
9. **खाना पकाने का ईंधन (Cooking fuel):** वंचित अगर खाना गोबर, लकड़ी या चारकोल के साथ पकाया जाता है
10. **संपत्ति स्वामित्व (Assets ownership):** वंचित अगर घर में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटरबाइक या रेफ्रिजरेटर में से एक से अधिक वस्तुएं नहीं हैं और उसके पास कार या ट्रक नहीं है

    एक व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि वे भारित संकेतकों के कम से कम एक तिहाई में वंचित है। गरीबी की तीव्रता संकेतकों के अनुपात को दर्शाती है, जिसमें वह वंचित है।

सूचकांक की गणना

एमपीआई की गणना इस प्रकार की जाती है:

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) = एच(H) × ए(A)

एच (H): उन लोगों का प्रतिशत जो एमपीआई पर गरीब हैं

ए (A): एमपीआई की औसत तीव्रता

अभ्यास प्रश्न

1. केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है
   (a) वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि
   (b) निरंतर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि
   (c) नाममात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि
   (d) आधार वर्ष की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि

2. किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है
   (a) सरकार द्वारा उपभोग और निवेश व्यय
   (b) विदेश में भारतीयों द्वारा उपभोग और निवेश व्यय
   (c) निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग और निवेश व्यय
   (d) उपरोक्त सभी द्वारा उपभोग और निवेश व्यय

3. खुली अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (Y) क्या है? (C, I, G, X, M) उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, कुल निर्यात, और कुल आयात के लिए क्रमशः हैं।)
   (a) Y = C + I + G + X
   (b) Y = C + I + G - X + M
   (c) Y = C + I + G + (X - M)
   (d) Y = C + I - G + X - M

4. वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि इसमें पूर्व में शामिल है-
   (a) आबादी का विकास
   (b) मूल्य स्तर में वृद्धि
   (c) मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
   (d) मजदूरी दर में वृद्धि

5. एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो
   (a) सकल राष्ट्रीय आय
   (b) शुद्ध राष्ट्रीय आय
   (c) सकल घरेलू उत्पाद
   (d) शुद्ध घरेलू उत्पाद

6. भारत के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय सभी भारतीयों की सामूहिक आय है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के बराबर है?
   (a) बाज़ार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
   (b) कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद
   (c) बाज़ार की कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
   (d) कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

7. सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को "सकल" कहा जाता है क्योंकि इसकी गणना से बाहर **नहीं** किया जाता है
   (a) उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की खपत
   (b) माल की खपत पर उपादान
   (c) देश में विदेशी मुद्रा की कमाई
   (d) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

8. भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
   (a) योजना मंत्रालय
   (b) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (c) गृह मंत्रालय
   (d) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

9. बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम आर्थिक वृद्धि दर का मुख्य कारण है
   (a) निवेश का कम दर
   (b) विदेशी निवेश का निम्न स्तर
   (c) कम पूंजी/उत्पादन अनुपात
   (d) उच्च पूंजी/उत्पादन अनुपात

10. भारत में, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?
   (a) योजना आयोग
   (b) वित्त मंत्रालय
   (c) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
   (d) आरबीआई

11. भविष्य में आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य समावेशी वृद्धि है। समावेशी वृद्धि की रणनीति ध्यान केंद्रित **नहीं** करती है
   (a) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

(b) पिछड़ी जातियों के बीच गरीबी में कमी
(c) जनजातीय आबादी के लिए आजीविका विविधता
(d) औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक उद्योग का प्रचार

12. रोजगार के उच्च स्तर की धारणा पैदा करने के बावजूद छिपी हुई बेरोजगारी आमतौर पर आय के निम्न स्तर की ओर ले जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी आम तौर पर मौजूद है
(a) विनिर्माण क्षेत्र में
(b) कृषि में
(c) लघु उद्योग में
(d) शहरी समाज में

13. जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों ने रोजगार खो दिया, तो इसे कहा जाता है
(a) मौसमी बेरोजगारी
(b) संरचनात्मक बेरोजगारी
(c) छिपी बेरोजगारी
(d) चक्रीय बेरोजगारी

14. अर्थव्यवस्था के मशीनीकरण और स्वचालन से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दर है?
(a) कुल आबादी में बेरोजगारों का प्रतिशत
(b) कुल श्रम बल में नियोजित का प्रतिशत
(c) कुल श्रम बल में बेरोजगारों का प्रतिशत
(d) गैर श्रम बल व्यक्तियों में बेरोजगारों का प्रतिशत

15. यदि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में बाज़ार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर और सरकारी उपादान के बीच संबंधों का सही वर्णन है:
(a) सरकारी उपादान > अप्रत्यक्ष कर
(b) सरकारी उपादान < अप्रत्यक्ष कर
(c) सरकारी उपादान = अप्रत्यक्ष कर
(d) सरकारी उपादान ≥ अप्रत्यक्ष कर

16. छिपी हुई बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है
(a) श्रम की कुल उत्पादकता शून्य है
(b) श्रम की औसत उत्पादकता शून्य है
(c) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, और
(a) यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शामिल है
(b) वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शामिल है
(c) अमेरिकी डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद शामिल है
(d) अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय शामिल है

18. बाज़ार की कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय और कारक लागत पर कुल राष्ट्रीय आय के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है?
(a) पूंजी की खपत
(b) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उपादान घटाने के बाद
(c) विदेश में अर्जित शुद्ध कारक आय
(d) शुद्ध उपादान अप्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद

19. फिलिप्स वक्र द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित किया गया है?
(a) वास्तविक और नाममात्र मजदूरी के बीच उल्टा संबंध

(b) मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच उल्टा संबंध
(c) नाममात्र मजदूरी और रोजगार की दर के बीच सकारात्मक संबंध
(d) मुद्रास्फीति की दर और नाममात्र मजदूरी के बीच सकारात्मक संबंध

20. लोरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह संबंध किसके बीच दिखाता है
(a) संपत्ति निर्माण और आय उत्पादन
(b) विभिन्न जनसंख्या समूह और उनकी संबंधित आय
(c) बेरोजगारी और मुद्रास्फीति
(d) मजदूरी, श्रम के घंटे, और अवकाश

21. उद्यमी द्वारा आपूर्तित उत्पादन के कारकों की लागत को किस रूप में जाना जाता है
(a) अस्पष्ट लागत
(b) स्पष्ट लागत
(c) स्थिर लागत
(d) परिवर्तनीय लागत

नोट: अस्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत से अलग है। स्पष्ट लागत में उद्यमी को दूसरों को भुगतान करना पड़ता है। परंतु, अस्पष्ट लागत में दूसरों को भुगतान नहीं करना पड़ता क्योंकि यह उद्यमी द्वारा आपूर्तित उत्पादन के कारकों की लागत होती है।

हालांकि, इसे भी लागत माना जाता है क्योंकि यदि उद्यमी किसी विशेष उद्यम में उत्पादन के कारक को आपूर्तित नहीं करता, तो वह इसका कोई अन्य उपयोग कर सकता था। इस प्रकार, उद्यमी ने अन्य उपयोग को नजरअंदाज करके उत्पादन के कारक को उद्यम में उपयोग किया है। परिणाम स्वरुप, वह कारक को उपयोग करने पर कारक की विकल्प लागत (opportunity cost) भुगत रहा है।

22. वृद्धि प्रक्रिया जो सतत है और व्यापक आधार पर लाभ प्रदान करती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, उसे कहा जाता है
(a) तेज़ वृद्धि
(b) समावेशी वृद्धि
(c) संतुलित वृद्धि
(d) सतत वृद्धि

23. राष्ट्रीय आय लेखांकन में, सकल कुल योग और शुद्ध कुल योग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है?
(a) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर
(b) स्थायी पूंजी की खपत
(c) मध्यवर्ती खपत
(d) अंतिम खपत व्यय

24. भारतीय अर्थव्यवस्था की घरेलू बचत (सकल) औसत दर वर्तमान में निम्नलिखित परिसर में है
(a) 15 से 20%
(b) 20 से 25%
(c) 25 से 30%
(d) 30 से 35%

25. निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा निम्न मानव विकास के लिए सबसे उपयुक्त है?
(a) लघु कृषि क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि की कम दर, और निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद
(b) उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का उच्च वृद्धि दर, और आय का असमान वितरण

(c) अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, खराब शैक्षणिक सुविधाएं, और निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद

(d) निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक बड़ी आबादी, और लघु कृषि क्षेत्र

26. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद $ 2 ट्रिलियन पार कर चुका है।
2. भारत में नाममात्र प्रति व्यक्ति आय 100,000 रुपये से अधिक है।
3. क्रय शक्ति समानता पर भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद है।
4. भारत में वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2 और 3

27. मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसके परिणाम स्वरुप, कृषि मजदूर बड़े पैमाने पर पिछड़े कृषि क्षेत्रों से शहरी विकसित क्षेत्रों की तरफ प्रवासन करते हैं।
2. रोजगार के मौसम के बाद, कई कृषि श्रमिक विशेष रूप से भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान बेरोजगार रहते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

28. बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में बहुआयामी रूप से गरीब आबादी का भाग इंगित करता है।
2. दक्षिण एशिया में, भारत की तुलना में केवल अफगानिस्तान में गरीबी के उच्च स्तर हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

नोट: बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने अफगानिस्तान को दक्षिण एशिया का सबसे गरीब देश बताया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर, दक्षिण एशियाई देश आरोही क्रम में निम्न अनुसार हैं: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव।

29. राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाता है?

1. मूल्यह्रास
2. उपादान
3. अप्रत्यक्ष कर
4. विदेश से शुद्ध कारक आय

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 2

(b) 1 और 2

(c) 1 और 3

(d) 3 और 4

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. शुद्ध घरेलू उत्पाद उसी वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो सकता है।
    2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसी वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद से हमेशा कम होता है।

    उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. सकल घरेलू उत्पाद की गणना की आय विधि में केवल उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त आय पर विचार किया जाता है।
    2. आय विधि के माध्यम से गणना की गई सकल घरेलू उत्पाद उसी वर्ष व्यय विधि के माध्यम से गणना की गई सकल घरेलू उत्पाद से कम होती है।

    उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

32. राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. सकल मूल्य संवर्धित (जीवीए) जीडीपी से कम होता है क्योंकि लगाए गए अप्रत्यक्ष कर उपादान से अधिक होते हैं।
    2. सकल मूल्य संवर्धित (जीवीए) उपभोक्ता के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि का माप है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) उत्पादक के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि का माप है।

    उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न तो 1 और न ही 2

33. निम्नलिखित जोड़ो पर विचार करें:

बेरोजगारी का प्रकार	**उदाहरण**
1. संरचनात्मक बेरोजगारी	साइकिल उद्योग से एक बेरोजगार कार्यकर्ता क्योंकि लोग अधिक कारें खरीद रहे हैं
2. चक्रीय	इस प्रकार की बेरोजगारी तब होती है जब वे सभी जो काम करना चाहते हैं उन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके काम के लिए बाज़ार में पर्याप्त मांग नहीं है।
3. प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी	सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए अपना काम छोड़ने वाला व्यक्ति।

ऊपर दिए गए जोड़ो में से कौन सा/से सही ढंग से मेल खाता है/खाते हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों और मात्रा दोनों में परिवर्तन को दर्शाता है।
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की केवल मात्रा में परिवर्तन दर्शाता है।
3. सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक (deflator)अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

नोट: अर्थशास्त्र में, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक (deflator) अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर का एक माप है। इसकी गणना नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा विभाजित करके और फिर 100 से गुणा करके की जाती है। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार मूल्य पर आधारित होता है।

जीडीपी अपस्फीतिकारक

$$= \frac{\text{नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद}}{\text{वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद}} \times 100$$

35. सकल घरेलू उत्पाद को देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर किए गए उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद गणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक क्षेत्र में है?
1. अंतरराष्ट्रीय जल में एक देश के निवासियों द्वारा संचालित मत्स्य जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिग।
2. विदेश में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान।
3. देश के निवासियों द्वारा स्वामित्व जहाज और विमान जो दो देशों के बीच परिचालन करते हैं।
4. विदेश में स्थित देश के निवासियों द्वारा स्वामित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

36. श्रम बाज़ार की स्थिति के आकलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल की संख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात है।
2. बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और कुल आबादी का अनुपात है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

37. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान की सटीकता को प्रभावित करता है?

1. गैर मुद्रीकृत क्षेत्र का उत्पादन
2. छोटे उत्पादकों या घरेलू उद्यमों की आय के बारे में आंकड़ो की अनुपलब्धता
3. रिपोर्ट नहीं की गई आय
4. मुद्रास्फीति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 4

38. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्वचालित रूप से आर्थिक कल्याण में वृद्धि को निहित नहीं करती है क्योंकि

1. आय का वितरण ज्ञात नहीं होता है
2. आर्थिक वृद्धि की दर ज्ञात नहीं होती है
3. प्रति व्यक्ति आय औसत की अवधारणा में कमी से पीड़ित है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: **(2010)**

पद	सर्वोपयुक्त वर्णन
1. मेल्टडाउन	स्टॉक कीमतों की गिरावट
2. मंदी (रिसेसन)	संवृद्धि दर की गिरावट
3. स्लो-डाउन	सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। **(2010)**

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विगत एक दशक में चार गुना वृद्धि हुई है।
2. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) ना तो 1 और ना ही 2

3. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2011)**
   1. विगत पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है।
   2. विगत पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) ना तो 1 और ना ही 2

4. UNDP के समर्थन से "ऑक्सफोर्ड निर्धनता एंव मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? **(2012)**
   1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वाथ्य, सम्पत्ति तथा सेवाओं से वंचन
   2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता
   3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिएः
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

5. X देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि **(2013)**
   (a) विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है
   (b) X में जनसंख्या वृद्धि होती है
   (c) X में पूंजी-निर्माण होता है
   (d) विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है

6. किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय **(2013)**
   (a) नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी
   (b) कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी
   (c) सभी व्यक्तियों के वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी
   (d) उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी

7. प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यत: अर्थ होता है कि **(2013)**
   (a) लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं
   (b) वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है
   (c) श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता शून्य है
   (d) श्रमिकों की उत्पादकता नीची है

8. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2015)**
   1. पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर लगातार बढ़ती रही है।
   2. पिछले दशक में बाज़ार क़ीमतों पर (रुपए में) सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसके द्वारा **(2018)**
   1. किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं।

2. देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है।
3. गोचर धन का संचय हो पाता है।
4. अगोचर धन का संचय हो पाता है।

उपर्युक्त कथनो में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 2 और 4
(d) 1, 3 और 4

10. उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी एक किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? **(2018)**

(a) कमजोर प्रशासन तंत्र
(b) निरक्षरता
(c) उच्च जनसंख्या घनत्व
(d) उच्च पूंजी - उत्पादन अनुपात

11. यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो **(2018)**

(a) विकल्प लागत शून्य होती है।
(b) विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है।
(c) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।
(d) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है।

12. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करतीं, यदि **(2018)**

(a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
(b) कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता हैं।
(c) निर्धनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।
(d) निर्यातों की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ते हैं।

उत्तर कुंजी ☑

अभ्यास प्रश्न

1. (c)	**2.** (d)	**3.** (c)	**4.** (b)	**5.** (a)	**6.** (d)	**7.** (a)	**8.** (d)	**9.** (d)
10. (c)	**11.** (d)	**12.** (b)	**13.** (b)	**14.** (c)	**15.** (b)	**16.** (c)	**17.** (d)	**18.** (b)
19. (b)	**20.** (b)	**21.** (a)	**22.** (b)	**23.** (b)	**24.** (d)	**25.** (c)	**26.** (d)	**27.** (c)
28. (c)	**29.** (a)	**30.** (d)	**31.** (a)	**32.** (a)	**33.** (d)	**34.** (d)	**35.** (c)	**36.** (d)
37. (a)	**38.** (c)							

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (a)	**2.** (b)	**3.** (d)	**4.** (a)	**5.** (c)	6. (b)	**7.** (c)	**8.** (b)	**9.** (b)
10. (d)	**11.** (d)	**12.** (c)						

समाधान: अभ्यास प्रश्न
और
पिछली प्रारंभिक परीक्षा

समाधान

अध्याय-1 आर्थिक वृद्धि और विकास (Economic Growth and Development)

अभ्यास प्रश्न

1. (c) कीमतों या उत्पादन में वृद्धि या दोनों में वृद्धि के कारण नाममात्र राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। इस प्रकार, केवल कीमतों में वृद्धि के कारण नाममात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है।
2. (d) आय निवेश और उपभोग का कुल योग है। भारत के निजी क्षेत्र, विदेश में भारतीयों और सरकार की कुल आय राष्ट्रीय आय के बराबर है।
3. (c) अर्थशास्त्र में, कुल व्यय राष्ट्रीय आय का एक माप है। इस प्रकार, कुल व्यय दी गई समयावधि के दौरान कारकों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्यय का कुल योग है। यह उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय, निवेश व्यय और अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा किए गए व्यय को संदर्भित करता है। खुली अर्थव्यवस्था में, कुल व्यय में निर्यात और आयात के बीच अंतर भी शामिल होता है।
4. (b) स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गणना आधार वर्ष में वस्तुओं / सेवाओं की कीमतों पर की जाती है इसलिए यह केवल तभी बढ़ सकती है जब किसी विशेष वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गणना उसी वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर की जाती है जिसमें वे उत्पादित होते हैं। यहां तक कि यदि भौतिक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो भी कीमत के स्तर में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है।
5. (a) किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे देश के बाहर या घरेलू क्षेत्र में हो, सकल राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है।
7. (a) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) से अधिक है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में से संपत्ति के मूल्यह्रास को घटाया नहीं जाता है।

   एनडीपी = जीडीपी - मूल्यह्रास

8. (d) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पर रिपोर्ट निकाली जाती है।

9. (d) उच्च वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात, बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम आर्थिक वृद्धि दर के लिए ज़िम्मेदार है। वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात जितना अधिक होगा, पूंजी के उपयोग से उत्पन्न उत्पादन उतना ही कम होगा।
10. (c) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय आय सांख्यिकी जारी करता है।
11. (d) समावेशी वृद्धि वह आर्थिक वृद्धि है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करती है। समावेशी वृद्धि मूल रूप से यह सुनिश्चित करती है कि हर किसी को आर्थिक वृद्धि से लाभ हो।
12. (b) भारतीय कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी का उच्च स्तर है।
13. (b) प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है।
15. (b) यदि बाज़ार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है, तो इसका अर्थ है कि आर्थिक सहायता (उपादान) अप्रत्यक्ष करों से कम है।

    बाज़ार मूल्य - अप्रत्यक्ष कर + उपादान = कारक लागत

17. (d) मानव विकास सूचकांक की निम्नलिखित आधार पर गणना की जाती है:
    (i) जन्म पर जीवन प्रत्याशा
    (ii) साक्षरता दर
    (iii) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (पीपीपी यूएस $)
18. (b) अप्रत्यक्ष कर - उपादान = बाज़ार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद - कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
19. (b) फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच उल्टा संबंध दिखाता है।
20. (b) लोरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। लोरेंज वक्र विभिन्न जनसंख्या समूह और उनकी संबंधित आय के बीच संबंध दिखाता है।
22. (b) वृद्धि प्रक्रिया जो अविरत है और व्यापक आधार पर लाभ प्रदान करती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, उसे समावेशी वृद्धि कहा जाता है।
25. (c) निम्न मानव विकास मतलब मानव विकास को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल संकेतकों पर खराब प्रदर्शन। इस तरह का खराब प्रदर्शन अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, खराब शैक्षिक सुविधाओं, और निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कारण होता है।
26. (d) कथन 1 सही है। भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
    कथन 2 सही है। 2016-2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 9.7 प्रतिशत बढ़कर ₹1,03,219 हो गई, जो` ₹94,130 थी।
    कथन 3 सही है। चीन और यूएसए के बाद, क्रय शक्ति समानता पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद (2016 तक $ 8.72 ट्रिलियन) है।
    कथन 4 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात लगभग 3 है जबकि भारत का वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात 4 के करीब है।
29. (a) सकल घरेलू उत्पाद + उपादान - अप्रत्यक्ष कर - विदेश से शुद्ध कारक आय = राष्ट्रीय आय।

30. (d) कथन 1 गलत है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद= सकल घरेलू उत्पाद - मूल्यह्रास।

कथन 2 गलत है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद= सकल घरेलू उत्पाद - भारत में विदेशियों को भुगतान की गई कारक आय + विदेश में भारतीयों को भुगतान की गई कारक आय।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद दो कारकों पर निर्भर करता है। यदि भारत में विदेशियों को भुगतान की जाने वाली कारक आय, विदेश में भारतीयों को दी गई कारक आय से अधिक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है; और इसके विपरीत यदि भारत में विदेशियों को भुगतान की जाने वाली कारक आय, विदेश में भारतीयों को दी गई कारक आय से कम है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इस प्रकार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से कम नहीं होता है।

31. (a) कथन 2 गलत है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य समान आता है।

33. (d) संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलावों के कारण होती है और प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा इत्यादि जैसे कारको से बढ़ती है।
मंदी की अवधि के दौरान चक्रीय बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास की अवधि के दौरान बेरोजगारी में गिरावट आती है।
जब कार्यकर्ता नौकरी छोड़कर बेहतर नौकरी की तलाश करता है, तो इसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है।

34. (d) कथन 1 सही है। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की गणना विशेष वर्ष की वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं।
कथन 2 सही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। यह केवल तब बढ़ सकती है जब किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बढ़ती है।

35. (c) आर्थिक क्षेत्र में शामिल है

- एक सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण होता है;
- सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत बंधुआ गोदाम और कारखानों सहित कोई भी समुद्री क्षेत्र;
- राष्ट्रीय वायु क्षेत्र, क्षेत्रीय जल, और अंतरराष्ट्रीय जल में महाद्वीपीय जल सीमा, जिस पर देश विशेष अधिकारों का आनंद उठाता है;
- अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत शेष दुनिया में क्षेत्रीय विदेशी अंतः क्षेत्र (दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैन्य अड्डों, वैज्ञानिक अड्डों, आदि);
- देश के निवासियों के स्वामित्व में अंतरराष्ट्रीय जल में तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य जमा भंडार।

आर्थिक क्षेत्र में बाह्यवर्ती विदेशी अंतः क्षेत्र (यानी, देश के अपने भौगोलिक क्षेत्र में अन्य देशों की सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, भारत के भीतर विदेशी दूतावास, वाणिज्य दूतावास, आदि भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं)।

36. (d) कथन 1 गलत है। श्रम बल भागीदारी दर की गणना श्रम बल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों की संख्या को श्रम बल में भाग लेने के लिए योग्य लोगों की कुल संख्या (कुल जनसंख्या नहीं) द्वारा विभाजित करके की जाती है। जो लोग नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं जैसे पूर्णकालिक छात्र, गृह निर्माता आदि; वे डेटा सेट का हिस्सा नहीं होंगे।
कथन 2 गलत है। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और कुल श्रम बल का अनुपात है।
37. (a) राष्ट्रीय आय अनुमान की सटीकता सभी उल्लिखित कारकों से प्रभावित होती है क्योंकि इन कारकों के सटीक मूल्य को निर्धारित करना मुश्किल है।
38. (c) कथन 2 गलत है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत देती है। इस प्रकार दूसरा कथन यह नहीं बताता कि कैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि स्वचालित रूप से आर्थिक कल्याण में वृद्धि को निहित नहीं करती है।
कथन 1 और 3 सही हैं। प्रति व्यक्ति आय केवल औसत आय बताती है। एक राष्ट्र का उच्च सकल घरेलू उत्पाद हो सकता है, लेकिन आय का वितरण कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित हो सकता है और शेष जनसंख्या गरीबी के तहत हो सकती है।

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (a) मंदी (रिसेसन) आमतौर पर जीडीपी में दो लगातार तिमाहियों में गिरावट से पहचानी जाती है। जब आर्थिक वृद्धि दर कम होती है, उसे स्लो-डाउन कहा जाता है।
2. (b) कथन 1 गलत है। 1990-2000 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.4% थी और 2000-2010 में 6.4% थी। जीडीपी चार गुना करने के लिए, देश को लगभग 15 वर्ष के लिए 10% से बढ़ना होगा।
कथन 2 सही है। निजी क्षेत्र की वृद्धि दर सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों) से कहीं अधिक है। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा पिछले 10 वर्षों में घट गया है।
3. (d) कथन 1 गलत है। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था। यह कथन स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि 2008 में वित्तीय संकट के कारण वृद्धि दर कम हो गई थी।
कथन 2 गलत है। यदि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ नहीं रही है, तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर भी लगातार बढ़ नहीं सकती।
4. (a) कथन 2 और 3 गलत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता, बजट घाटे की मात्रा, और राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं हैं।
5. (c) आर्थिक वृद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है: पूंजी निर्माण और वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात।
6. (b) कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित सामूहिक आय है। इस आय को उपभोग और निवेश व्यय में आगे बांटा जा सकता है।
7. (c) प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां मौजूद है जहां अतिरिक्त कार्य बल उत्पादन के प्रति कुछ भी योगदान नहीं दे रही है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है।
8. (b) कथन 1 गलत है। पिछले दशक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (आर्थिक वृद्धि दर) लगातार नहीं बढ़ती रही है।
कथन 2 सही है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

9. (b) यह सवाल थोड़ा उलझन वाला है। यह प्रशन उस प्रक्रिया के बारे में बात करता है जो मानव पूंजी निर्माण की व्याख्या करती है।
कथन 2 सही है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जो देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि सक्षम बनाती है।
कई लोग कथन 4 को सही मानते हैं। हालांकि, कॉपीराइट, पेटेंट इत्यादि जैसे अमूर्त संपत्ति का संचय मानव पूंजी निर्माण का परिणाम है और यह मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। इस प्रकार, कथन 4 गलत है।
इसी प्रकार, कथन 1 और 3 भी गलत हैं क्योंकि वे भी मानव पूंजी निर्माण का परिणाम हैं।

11. (d) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है।
विकल्प (a) गलत है। क्योंकि वस्तु 'निःशुल्क' दी जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी विकल्प लागत शून्य है। इस मामले में, अगर सरकार जनता को निःशुल्क वस्तु नहीं दे रही है, तो यह कहीं और पैसे का उपयोग कर सकती है।
विकल्प (b) गलत है। प्रत्येक वस्तु की एक लागत है। इस प्रकार, विकल्प लागत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
विकल्प (c) गलत है। एक बार एकत्रित कर प्राप्तियां सरकार से संबंधित हैं। इस प्रकार, उनके आगे के उपयोग में सरकार पर विकल्प लागत पड़ती है।
विकल्प (d) सही उत्तर है। यहां विकल्प लागत यह है कि सरकार निःशुल्क वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जो खर्च कर रही है। अगर सरकार ने निः शुल्क वस्तुओं को नहीं दिया होता, तो यह किसी भी अन्य तरीके से उसी धन का इस्तेमाल कर सकती थी।

12. (c) निर्धनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।
आर्थिक विकास न केवल जीएनपी, जीडीपी जैसे मात्रात्मक संकेतकों पर विचार करता है बल्कि जीवनस्तर, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि जैसे गुणात्मक संकेतक को भी ध्यान में रखता है।

अध्याय-2 भारत की कराधान प्रणाली

अभ्यास प्रश्न

3. (b) अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा लाफर वक्र विकसित किया गया था। वक्र विभिन्न कर दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच संबंध बताता है।

5. (b) उच्च आय वाले लोगों पर उच्च कर लगाने (प्रगामी कराधान) और कम आय वाले लोगों पर बड़ी राशि खर्च करने (प्रतिगामी व्यय) के माध्यम से आय का सबसे उत्तम पुनर्वितरण किया जा सकता है।

10. (d) राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर (वैट) लगाया, एकत्रित किया और विनियोजित किया जाता है। इसे जीएसटी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

13. (b) कथन 1 गलत है। जीएसटी के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विभाजित है।

14. (c) इनपुट क्रेडिट व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं या सेवाओं पर उपलब्ध नहीं है।

17. (b) कथन 1 गलत है। एक संपत्ति डीलर द्वारा स्टॉक के रूप में रखे फ्लैटों की बिक्री से उत्पन्न लाभ पूंजीगत लाभ नहीं है। डीलर का व्यवसाय फ्लैट बेचना खरीदना है।

मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति

एक अच्छा उत्तर निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है।

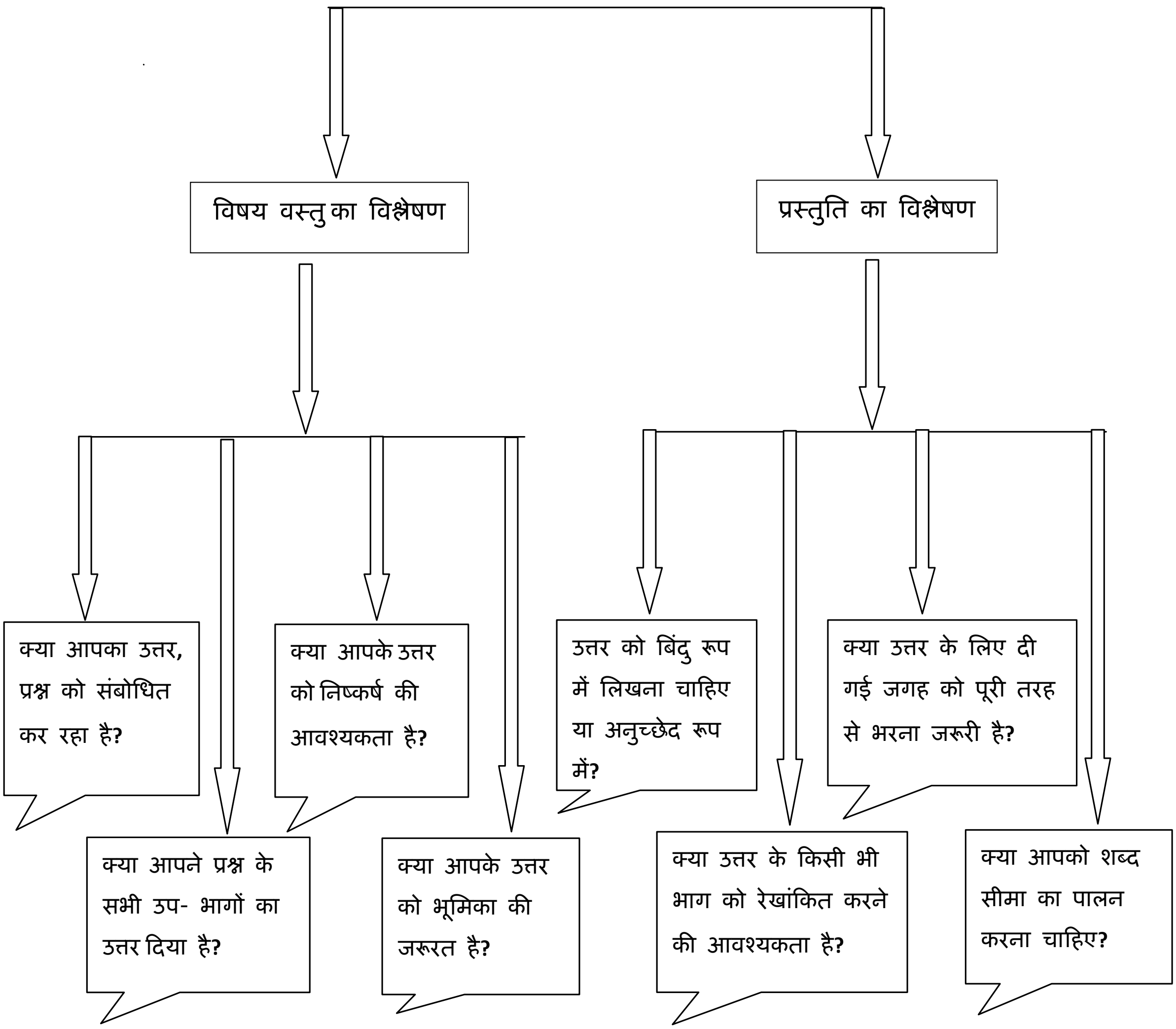

आइए, हम चित्र में दिए गए पहलुओं पर विचार करते हैं।

1. क्या आपका उत्तर, प्रश्न को संबोधित कर रहा है?

कम अंक आने का सबसे सामान्य कारण अभ्यर्थी की प्रश्न को समझने की क्षमता में कमी होना है।

क्या आपने कभी भी किसी अभ्यर्थी को यह कहते हुए सुना है कि मैंने लगभग सभी (या सभी) प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सका?

संभवतया: आप ऐसे अभ्यर्थी से मिले हैं, जिसके उत्तरों ने प्रश्नों को संबोधित नहीं किया; अर्थात उसने प्रश्नों को पूरी तरह से समझे बिना ही उत्तर लिख दिए।

प्रश्न को ठीक से कैसे संबोधित करना है, यह समझने के लिए हम प्रत्येक प्रश्न को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: 'कथन' और 'अनुदेश'।

उदाहरण के लिए

राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों की सफलता पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। **(2014)**

उपर्युक्त प्रश्न में, 'राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों, जो वाहनों की आवाजाही के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती हैं' कथन है और अनुदेश **'आलोचनात्मक चर्चा कीजिए'** है। मान लीजिए कि एक उम्मीदवार राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की सफलता, जो वाहनों की आवाजाही के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती हैं, या परिवहन नीति के संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करता है। ऐसे उम्मीदवार के अंको में गंभीर रूप से कटौती की जाएगी।

इस प्रश्न की आलोचनात्मक चर्चा में विषय वस्तु के पक्ष और विपक्ष स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्रश्न राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के संबंध में सरकार की विभिन्न रणनीतियों की सफलता के पक्ष और विपक्ष की मांग करता है, जो 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है।

यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि किसी विशेष अनुदेश को किसी प्रश्न के उप-भाग से जोड़ा जा सकता है। एक प्रश्न में, प्रत्येक उप-भाग के साथ पृथक अनुदेश हो सकता है।

वे कौन से अनुदेश हैं, जिनका प्रयोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किया जाता है? इन अनुदेशों से क्या तात्पर्य है?

यहां आपके लिए एक साधारण सूची दी जा रही है। आगे के पन्नों में, हम पिछले साल के प्रश्नों को हल करते हुए इन 'अनुदेशों' के अनुसार उत्तर लिखने सीखेंगे।

1. **गणना करें:** कई चीजों को एक-एक करके बताएं या चीजों की सूची दें। उदाहरण के लिए,
   भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं सम्भावनाओं को गिनाइए। **(2016)**
2. **चिन्हांकित करें (प्रकाश डालिए):** विशिष्ट रूप से दर्शाना।
3. **सारांश:** सारांश दें, संक्षिप्त करना।
4. **चर्चा (विवेचना) करें:** अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखकर, विषय को विस्तार से लिखिए। उदाहरण के लिए,
   यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को स्वीकृति दे दी थी, पर इस निवेश में एक वर्ष पश्चात् भी कोई उन्नति नहीं हुई है। कारणों की विवेचना कीजिए। **(2013)**

पिछले वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)
समाधान के साथ

1. समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, नए कंपनी के बिल, 2013 ने 'सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व' को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों की भी चर्चा करें। (2013)

Sol. प्रश्न समाधान 2013 के सामयिकी मामलों पर आधारित है।

2. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। (2013)

Sol.

प्रश्न का विश्लेषण	
समालोचनात्मक विवेचन कीजिए	इस प्रश्न को हल करने के लिए समस्या या स्थिति को विभिन्न भागों में तोड़ने और इन भागों के पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है।
उप-भागों की संख्या	तीन उप-भाग भाग I - वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के कारण भाग II - उसके प्रमुख प्रावधानों का समालोचनात्मक विवेचन भाग III- उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन
लिखने का तरीका	बिंदु रूप
निष्कर्ष का महत्व	आवश्यक

वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 को प्रारंभ करने के कारण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 को केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर राजकोषीय अनुशासन लाने के लिए अपनाया गया था। विशेष रूप से, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 को अपनाने के निम्नलिखित कारण थे:

1. भारी राजकोषीय और राजस्व घाटे भारत की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठा रहे थे।
2. घाटे और ऋण के उच्च स्तर ने नए उधार लेने की लागत बढ़ा दी थी।
3. भारत एक संघीय देश है। यह आवश्यकता थी कि केंद्र सरकार के पास राज्यों की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने का साधन होना चाहिए।

एफआरबीएम अधिनियम तथा नियम के प्रमुख प्रावधान

1. हर वर्ष, सरकार राजस्व घाटे को 0.5% से कम करेगी और 2007-08 तक इसे खत्म कर देगी।
2. हर वर्ष, सरकार राजकोषीय घाटे को 0.3% से कम करेगी और 2007-08 तक इसे 3% तक लाएगी।
3. केंद्र सरकार की कुल देनदारियां सालाना 9% से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।
4. केंद्र सरकार पीएसयू और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए, सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक, ऋणों की गारंटी नहीं देगी।

5. राज्य सरकारों को अपने स्वयं के एफआरबीएम अधिनियमों को तैयार करने के लिए कहा गया था। जिन राज्यों ने अपने स्वयं के एफआरबीएम अधिनियमों को तैयार किया, उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आगे ऋण लेने की स्वायत्तता दी गई है।

एफआरबीएम अधिनियम की आलोचना

1. **अनुपालन को लागू करने के उपाय:** इसके लिए वित्त मंत्री को संसद के समक्ष वित्त और व्यय की त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता है। लक्ष्यों से विचलन संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अनुपालन की विफलता के लिए कोई अन्य उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
2. वित्तीय अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता सरकार को सामाजिक व्यय पर कटौती करने के लिए मजबूर कर सकती है।
3. **बजट से बाहर के विषय (ऑफ बजट आइटम)** जैसे कि तेल बांड सरकारी व्यय में नहीं गिने जाते हैं।
4. **वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव**: 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण, इस अधिनियम के तहत समय सीमा 2009 में स्थगित कर दी गई थी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर काबू पाने के बाद, एफबीआरएम अधिनियम 2012-13 में दोबारा लागू किया गया था, लेकिन सख्ती से नहीं।
5. **लचीलेपन की आवश्यकता**: हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने सरकार के संचालन में लचीलापन लाने के लिए विशिष्ट निश्चित आंकड़ों के बजाय एफआरबीएम अधिनियम के तहत लक्ष्य के परिसर की मांग की है।

निष्कर्ष

एफआरबीएम अधिनियम वित्तीय अनुशासन की चिंताओं को आगे लाया है। हालांकि, इस अधिनियम में संघ और राज्यों द्वारा अनुपालन के लिए तंत्र की कमी है।

3. 'कर खर्च' (Tax expenditure) का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजटी-संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। (2013)

Sol.

प्रश्न का विश्लेषण	
विवेचना कीजिए	अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखकर, विषय को विस्तार से लिखिए।
उप-भागों की संख्या	तीन उप-भाग भाग I 'कर खर्च'(Tax expenditure) का अर्थ भाग II गृह क्षेत्र का उदाहरण भाग III कर खर्च के बजटी-संबंधी नीतियों पर प्रभाव
लिखने का तरीका	बिंदुओं तथा अनुच्छेदों का मिश्रण
निष्कर्ष का महत्व	आवश्यक नहीं है

कर खर्च सरकार द्वारा अपने नीति लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए छोड़ी गई राशि है। सरल शब्दों में, सरकार कर में बहुत सारी रियायतें, राहत, छूट और कटौती दे सकती है, और ऐसा करके, सरकार उद्योग या व्यवसाय, निवेश इत्यादि को बढ़ावा देती है।

गृह क्षेत्र में कर खर्च के उदाहरण

उदाहरण के लिए, गृह क्षेत्र में, सरकार की कई नीतियां हैं जो "कर खर्च" के अंतर्गत आती हैं। कुछ कर छूट निम्नानुसार हैं:

1. अगर एक नए गृह में राशि निवेश की जाती है तो पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जाती है।
2. अक्सर, उत्पाद शुल्क से छूट तैयार मिश्रित कंक्रीट के निर्माताओं को प्रदान की जाती है (जिसका उपयोग आवास के लिए किया जाता है)।
3. अगर किसी ने गृह ऋण लिया है, तो उसे ऋण की चुकौती पर आयकर से कटौती मिलती है।

कर खर्च बजट नीतियों को कैसे प्रभावित करता है?

कर खर्च सरकार के बजट को कई तरीकों से प्रभावित करता है। ऐसी हर नीति सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाती है। कर खर्च से संबंधित, निम्नलिखित विभिन्न प्रभाव हैं:

1. कर खर्च से संबंधित प्रावधानों का कर योग्य आय को बदलने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
2. कर व्यय के कारण छोड़ा गया धन अक्सर बहुत अधिक होता है, लेकिन लाभ समाज के कुछ वर्गों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
3. कर खर्च के लाभ पर समाज के समृद्ध वर्गों द्वारा दावा किया जाता है, और गरीबों को आमतौर पर ऐसी नीतियों से लाभ नहीं होता है।

   इस प्रकार, कर खर्च बजटीय नीतियों को कई तरीकों से प्रभावित करता है।

4. भारत में माल और सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के लिए मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। (2013)

Sol. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरूआत के साथ इस प्रश्न का भाग II संदर्भ से बाहर है।

प्रश्न का विश्लेषण	
पहले उप-भाग के साथ अनुदेश, विवेचना कीजिए	अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखकर, विषय को विस्तार से लिखिए।
दूसरे उप-भाग के साथ अनुदेश, समालोचनात्मक वर्णन	विभिन्न भागों का विश्लेषण
उप-भागों की संख्या	दो उप-भाग भाग I - भारत में माल और सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के लिए मूलाधार भाग II - माल और सेवा कर (GST) को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन
लिखने का तरीका	बिंदु रूप
निष्कर्ष का महत्व	आवश्यक नहीं है

परिशिष्ट

I

सरकारी योजनाएं

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

केंद्र सरकार की योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (Central sector schemes) पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची 7 के तहत संघीय सूची में उल्लिखित विषयों पर बनाई जाती हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) को केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है तथा वित्तपोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। प्रत्येक योजना के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण के अनुपात में भिन्नता हो सकती है, जैसे 50:50, 70:30, 75:25 या 90:10। आमतौर पर, केंद्र सरकार पर अधिक बोझ पड़ता है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जब तक वे केंद्र की जिम्मेदारी के क्षेत्र में नहीं आती हैं, यानी संघ सूची में नहीं आती। भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र प्रायोजित योजनाएं तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं कल्याणकारी गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती हैं।

प्रत्येक पांच वर्षीय योजना की अवधि के अंत में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाती है। हालांकि, पांच वर्षीय योजनाओं की अनिरन्तरता के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं की अंतिम तिथि वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यकाल के साथ संलग्न होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा को छोड़कर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम तिथि पूर्व निर्धारित होती है। हालांकि, यह तिथि समीक्षा पर आगे बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बीच अंतर

मानदंड	केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
वित्तपोषण	100% केंद्र सरकार द्वारा	केंद्र और राज्यों के बीच साझा
कार्यान्वयन	केंद्र सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा
विषय	संघ सूची के तहत उल्लिखित विषय पर	राज्य सूची के तहत उल्लिखित विषय पर
अंतिम तिथि	आमतौर पर, इन योजनाओं की अंतिम तिथि नहीं होती है।	आमतौर पर, इन योजनाओं की अंतिम तिथि होती है।

इस परिशिष्ट में उन योजनाओं का विवरण शामिल है जो वर्तमान में कार्यान्वयन में हैं। योजनाओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं
2. वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं

पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं

a. भारत निर्माण

भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों के साथ साझेदारी में है। यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है।

इसमें छह घटक हैं:

1. सिंचाई
2. सड़कें
3. आवास
4. जल आपूर्ति
5. विद्युतीकरण
6. दूरसंचार संयोजकता

b. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, एमजीएनआरईजीएस/मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। ग्रामीण परिवार का एक वयस्क सदस्य, जो अकुशल हस्त काम करने के लिए तैयार है, को मौजूदा मजदूरी दर पर योजना के तहत रोजगार दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अन्य विशेषताएं:

1. मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक कानूनी अधिकार है। इस प्रकार, यह योजना अन्य कल्याण योजनाओं से अलग है क्योंकि यह केवल कल्याण आधारित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार प्रदान करती है।
2. प्रत्येक योग्य व्यक्ति जो काम के लिए पंजीकरण करवाता है, उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा, सरकार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होगा। योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के

बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित किया जाता है; जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, जहां अनुपात 90:10 है। बेरोजगारी भत्ते के मामले में, केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच खर्च साझा करने का अनुपात 10:90 है।

3. इसके अलावा, काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होता है। भुगतान सीधे बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में किया जाता है, और नकद के रूप में नहीं। यह प्रावधान भुगतान प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए शामिल किया गया है।
4. अधिनियम ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और मशीनरी के न्यूनतम उपयोग के लिए निर्देशित करता है।
5. इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले काम की प्रकृति में जल संरक्षण परियोजनाएं, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, भूमि विकास, ग्रामीण सड़कें आदि शामिल हैं।
6. श्रम को प्राथमिकता देने के लिए सामग्री का उपयोग सीमित किया गया है। श्रम की तुलना में सामग्री का उपयोग 40: 60 के अनुपात से अधिक नहीं हो सकता, (सामग्री 40 और श्रम 60) ।

c. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan, एसएसए) का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का समयबद्ध सार्वभौमिकरण है, जैसा कि भारत के संविधान में 86 वें संशोधन द्वारा अनिवार्य है, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009 पारित किया गया था। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय मुख्य तौर पर ज़िम्मेदार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं:

1. 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
2. यहां तक कि निजी स्कूलों को अपनी कक्षा की संख्या का 25% यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से कमजोर और वंचित वर्गों से लेना होगा। सरकार इन 25% आरक्षित सीटों के लिए निजी स्कूलों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। मुआवजा सरकारी स्कूलों में प्रति शिक्षा औसत लागत की दर से प्रदान किया जाएगा (सिवाय तब, जब निजी स्कूल में प्रति विद्यार्थी लागत कम हो)।
3. 25% कोटे में कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती है। आरक्षित सीटों पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
4. सभी विद्यालयों को इस अधिनियम में निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुसरण करना होगा और कोई भी स्कूल जो इनको 3 वर्षों के भीतर पूरा नहीं करता है, उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   सभी निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। असफल रहने पर उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा और यदि वे फिर भी कार्य करते रहेंगे, तो उन्हें प्रतिदिन जुर्माने के रुप में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण के मानदंडों और मानकों को भी निर्धारित किया गया है।

5. प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल या निष्कासित नहीं किया जा सकता है। इस नीति को लोकप्रिय रूप से 'नो डिटेंशन पॉलिसी' कहा जाता है।
6. इस ऐतिहासिक अधिकार के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का दायित्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) को सौंपा गया है।

d. मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) स्कूल के बच्चों में अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने का प्रयास करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस योजना के लिए मुख्य मंत्रालय है। इस योजना में सरकारी स्कूलों, सरकार द्वारा समर्थित स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। इन छात्रों को खाद्यान्न आपूर्ति मुफ्त में की जाती है।

प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रति बच्चे प्रति दिन 100 ग्राम खाद्यान्न, और ऊपरी प्राथमिक चरण के छात्रों को प्रति बच्चे प्रति दिन 150 ग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। यदि पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया जाता है, तो प्रति माह प्रति छात्र 3 किलो कच्चा अनाज वितरित किया जाता है।

e. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services, ICDS) का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय के बच्चों को एकीकृत तरीके से सेवाएं प्रदान करना है ताकि उचित वृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके। आईसीडीएस (ICDS) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 1975 में शुरू किया गया था। वर्तमान में, आईसीडीएस बाल विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। यह शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

आईसीडीएस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लागू किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक स्थानीय समुदाय महिला है जो आईसीडीएस के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रमुख मंत्रालय है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 0-6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए छः सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं हैं:

1. पूरक पोषण
2. टीकाकरण
3. स्वास्थ्य जांच
4. संदर्भ सेवाएं
5. मां को पोषण शिक्षा - मां को पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि माता बच्चों को उचित रूप से खिला सके।
6. 3-6 वर्षों के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा।

f. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission), जो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, को 2005 में शुरू किया गया था, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा कर सके। 2013 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission, एनयूएचएम) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप-मिशन के रूप में शुरू किया गया था।

मिशन का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के साथ एक विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली स्थापित करना है। मिशन स्वास्थ्य के निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इन निर्धारकों में पानी, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लिंग समानता शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ प्रमुख उपक्रम इस प्रकार हैं:

1. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist, आशा) एक स्थानीय महिला है जिसे निम्न स्वास्थ्य सेवाओं को वितरित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है:

1. मौखिक निर्जलीकरण समाधान (Oral Rehydrate Solution) जैसी बुनियादी दवाओं का वितरण।
2. टीकाकरण
3. स्वास्थ्य जांच
4. संदर्भ सेवाएं, आदि

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) से जनन करने की उम्मीद नहीं है। सरकार संस्थागत जनन को बढ़ावा देती है।

2. जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana, जेएसवाई) का उद्देश्य महिलाओं को अस्पताल जैसी संस्थागत व्यवस्था में पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करके मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना के अंतर्गत, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में जन्म देने के लिए योग्य गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान की जाती है।

जेएसवाई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो जनन और जनन के बाद देखभाल के साथ नकदी सहायता को एकीकृत करती है। इस कार्यक्रम में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार और गरीब महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी बन जाते हैं।

जेएसवाई से जुड़े आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिकाएं निम्नानुसार हैं:

a. योजना के लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिलाओं की पहचान करना और पूर्व जन्म जांच (Ante natal checkup) के लिए पंजीकरण करवाना,

b. महिला को कम से कम तीन पूर्व जन्म जांच प्रदान करवाने में सहायता,

c. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए परामर्श देना,

d. लाभार्थी महिलाओं को पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना और जब तक उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती तब तक उनके साथ रहना,

e. 14 सप्ताह की आयु तक नवजात शिशु के टीकाकरण की व्यवस्था करना